● वर्ष-4
● अंक-88
रायपुर, गुरुवार
21 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» बूम पर है वकालत का प्रोफेशन...

एग्जिट पोल के नतीजे....

महाराष्ट्र में भाजपा को बढ़त, झारखंड में भी परिवर्तन के आसार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। मैट्रीज के अनुसार, महायुति सरकार महाराष्ट्र में वापसी करती दिख रही है। वहीं, महाविकास अघाड़ी के लिए ये नतीजे निराश करने वाले हैं। मैट्रिज की मानें तो महायुत को 150 से 170 तो महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिली दिख रही हैं। वहीं, मैट्रिज ने झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार आती दिख रही है।

एसएएस के एग्जिट पोल के नतीजों ने चौंकाया, महाविकास अघाड़ी को किया आगे

अभी तक के एग्जिट पोल के नतीजे जहां महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार बनवा रहे थे, लेकिन इस बीच एक सर्वे ने महाविकास अघाड़ी को खुश होने का मौका दिया है। एसएएस के एग्जिट पोल ने अपने सर्वे में महाविकास अघाड़ी को 147-155 तो महायुति को 127-135 सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 10-13 सीटें जाती दिख रही हैं।

एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत

झारखंड को लेकर एक्सिस माय इंडिया ने एकदम उलट नतीजे दिए हैं। इनके नतीजे की मानें तो जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को 53 तो बीजेपी गठबंधन को 25 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं।

चाणक्य रणनीतियां के पोल नतीजों में झारखंड में किसकी सरकार

झारखंड में चाणक्य रणनीतियां की मानें तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 45-50 सीटें हासिल कर सकता है, तो वहीं जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 35-38 सीटें मिल सकती हैं।

पोल डायरी के एग्जिट पोल में भी महायुति सरकार, महाविकास अघाड़ी को निराशा

महाराष्ट्र में पोल डायरी के एग्जिट पोल के नतीजे भी महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने की बात कही है। पोल डायरी की मानें तो बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को 122-186 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को 69-121 सीटें मिलती दि रही हैं। पीएमएआरक्यू के सर्वे में भी महाराष्ट्र में महायुति सरकार की बनती दिख रही है। महायुति को

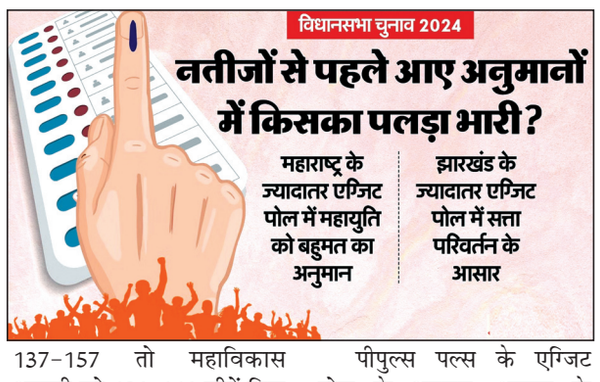

137-157 तो महाविकास अघाड़ी को 126-146 सीटें मिल सकती हैं।

टाइम्स नाउ के जेवीसी एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए-इंडिया में कांटे की टक्कर

झारखंड के लिए टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच करीबी मुकाबला होने का संकेत दिया है। भाजपा + गठबंधन को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेएमएम + गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल से संकेत मिलता है कि छोटे दल या निर्दलीय लगभग 1 सीट हासिल कर सकते हैं।

झारखंड में बीजेपी की सरकार, पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में दावा

पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन झारखंड में सत्ता हासिल कर सकता है। 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 सीटों के साथ, एनडीए के 42 से 48 सीटों के बीच जीतने का अनुमान है। एनडीए की सहयोगी आजसू पार्टी को 2 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। जेएमएम के नेतृत्व वाले भारत गठबंधन के 16 से 23 सीटों के बीच जीतने का अनुमान है,जिसमें कांग्रेस को 8 से 14 सीटें मिलने की संभावना है।

चाणक्य के एग्जिट पोल में महायुति की सरकार

मैट्रिज के बाद अब चाणक्य एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के लिए मजबूत प्रदर्शन का अनुमान लगाया है, जिसमें 288 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के लिए 150 से 160 सीटें जीतने की संभावना है। विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के 130 से 138 सीटों के बीच सुरक्षित होने की उम्मीद है, जो दोनों गठबंधनों के बीच करीबी मुकाबले का संकेत देता है। छोटे दलों और निर्दलीयों के 6 से 8 सीटें जीतने का अनुमान है, जो संभावित रूप से अंतिम परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं।

झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार, मैट्रिज ने दे दिए नतीजे

मैट्रिज के अनुमान के अनुसारा,भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 81 सदस्यीय विधानसभा में 42 से 47 सीटों के बीच मिलने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटों के बीच मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र में महायुति सरकार,मैट्रिज ने जारी कर दिए नतीजे

मैट्रिज के ताजा एक्जिट पोल के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में स्पष्ट जीत हासिल करता दिख रहाव है। इसके अनुसार, 288 सदस्यीय विधानसभा में महायुति को 150 से 170 सीटों के बीच का अनुमान है। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को 110 से 130 सीटों के बीच जीतने की उम्मीद है।

हम भारी बहुमत के साथ वापसी करेंगे- भाजपा उम्मीदवार नितेश राणे

कंकावली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नितेश राणे ने कहा कि अगर कोई विधायक या सांसद हमेशा अपने मतदाताओं के संपर्क में रहता है तो यह कोई समस्या नहीं है। हम जमीन से जुड़े हुए हैं। मेरा पूरा परिवार कोंकण क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लोग मेरा विस्तारित परिवार हैं। यहां के लोग जानते हैं कि हमारा परिवार 1990 से उनके लिए काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान बेहतर रहा है। हमारे लिए,लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यह चुनाव चुनौतीपूर्ण नहीं था क्योंकि हम अपनी ओर से किए गए काम को लेकर आश्वस्त थे। मुझे लगता है कि हम भारी बहुमत के साथ वापसी करेंगे।

महाराष्ट्र-झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, खत्म हुई वोटिंग, अब नतीजों का इंतजार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और झारखंड के दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, शाम 5 बजे तक, झारखंड (द्वितीय चरण) 67.59% और महाराष्ट्र में 58.22% मतदान दर्ज किया गया। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, गढ़चिरौली जिले में सबसे अधिक 69.63% मतदान हुआ, जबकि मुंबई शहर में सबसे कम 49.07% मतदान हुआ। ठाणे में 49.76% मतदान हुआ। ईसीआई द्वारा साझा किए गए अन्य मतदान आंकड़ों में शामिल हैं- मुंबई उपनगरीय 51.76%, नागपुर 56.06%, औरंगाबाद 60.83%, पुणे 54.09%, नासिक 59.85%, सतारा 64.16%, धुले 59.75%, पालघर 59.31%, रत्नागिरी में 60.35%, नांदेड़ में 55.88%, और लातूर 61.43% पर। अधिकारियों ने बताया कि 9.7 करोड़ से अधिक मतदाता मैदान में मौजूद 4,136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा 149 सीट पर, शिवसेना 81 सीट पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा 59 सीट पर चुनाव लड़ रही है। विपक्षी गठबंधन एमवीए में शामिल कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना (यूबीटी) ने 95 और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने 86 उम्मीदवार उतारे हैं।

महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024

भारतीय महिला हॉकी टीम ने दोहराया इतिहास

चीन को 1-0 से हराकर फिर बनी एशियन चैंपियन

नई दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास को दोहराया है। दरअसल, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर भारत ने फिर से चैंपियन बन गया है। चीन के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और गेंद को ज्यादातर समय अपने नियंत्रण में रखा और दूसरी तरफ चीन के खिलाड़ी मैच में एक भी गोल करने में नाकामयाब रहे। भारत ने तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है और साउथ कोरिया की बराबरी कर ली है। बता दें कि, साउथ कोरिया ने भी 3 बार ट्रॉफी का टाइटल तीन बार जीता था। हरेंद्र सिंह के हेड कोच रहते हुए भारतीय महिला टीम ने अपना पहला खिताब जीता। वहीं भारत की तरफ से एकमात्र गोल दीपिका ने किया है।

सेना हटने के बाद पहली बार मिले भारत-चीन के रक्षा मंत्री

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह लाओस की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वह 10 देशों के समूह आसियान और उसके कुछ वार्ता साझेदारों के समूह की बैठक में भाग ले रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस के दौरान चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लेंगे। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचार-विमर्श की बात कही जा रही है। सूत्रों ने बताया कि सिंह आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक(एडीएमएम-प्लस) में क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर भारत का रुख पेश कर सकते हैं।

प्रमुख समाचार

राहुल ने तेलंगाना सरकार की पहल की प्रशंसा की

हैदराबाद । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अस्थायी कर्मियों के कल्याण के लिए कानून बनाने के तेलंगाना सरकार के कदम की सराहना की और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मसौदा कानून के लिए राज्यव्यापी सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने का आग्रह किया। रेड्डी को लिखे पत्र में गांधी ने कहा कि वह हैदराबाद की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण (राज्य में चल रहे) के लिए जीवंत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। गांधी ने कहा, '' मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप गिग वर्कर्स के लिए मसौदा कानून पर भी इसी तरह के राज्यव्यापी सार्वजनिक परामर्श आयोजित करें। सभी पक्षों की सुनवाई से मजबूत, प्रभावी और सार्थक कानून सुनिश्चित होगा। यह प्रक्रिया इस क्षेत्र के लिए भविष्य के विनियमनों को भी मजबूत बनाने में मदद कर सकती है।'' गिग वर्कर्स ऐसे कर्मियों को कहा जाता है जो आनलाइन प्लेटफार्म, विनिर्माण, पेट्रोल पंप, सेवा क्षेत्र आदि में बिना विशेष सुविधाओं के काम करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा बनकर खुशी होगी।

क्या केंद्रीय बजट में दिखाई देगी जी-20 की आम सहमति?

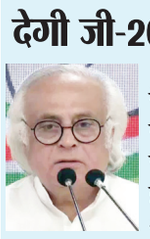

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को सवाल उठाया कि क्या भारत में जी20 की घोषणापत्र में नेताओं द्वारा की गई सहमति के अनुसार अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ (यूएचएनआई) व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंगलवार को अपनाए गए जी20 रियो डी जेनेरियो नेताओं के घोषणापत्र के पैरा 20 में लिखा था कि हम अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले केंद्रीय बजट 2025-26 को 75 दिनों से भी कम समय में संसद में पेश करेंगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या यह सहमति बजट में दिखाई देगी? उन्होंने कहा कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 334 अरबपति हैं, जिनमें से प्रत्येक की कुल संपत्ति एक बिलियन डॉलर से ज्यादा है और यह संख्या बढ़ रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर आरोप लगाती रही है कि यह अमीरों के लिए काम कर रही है और इसके शासन में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं।

मोदी दुर्लभ क्षमता वाला एक उल्लेखनीय नेता: अलेक्जेंडर

नई दिल्ली। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु प्रसिद्ध रूसी राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक, अलेक्जेंडर डुगिन वर्तमान में एक निजी मिशन के लिए भारत में हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए, जिनमें दुनिया कैसे बदल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत का भविष्य और दुनिया हिंदुत्व के उदय को कैसे देखती है। डुगिन ने पीएम मोदी को विभिन्न क्षेत्रों और विचारधाराओं के विश्व नेताओं के साथ संबंधों को संतुलित करने की दुर्लभ क्षमता वाला एक उल्लेखनीय नेता बताया। उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और सम्मानित राष्ट्र में बदलने के लिए पीएम मोदी की सराहना की। अलेक्जेंडर दुगिन न केवल प्राथमिक पुतिन के गुरु माने जाते हैं बल्कि रूस के नीति निर्धारक भी माने जाते हैं। पुतिन हर फैसले से पहले अलेक्जेंडर दुगिन से सलाह लेते हैं। यूक्रेन जंग पर दुगुने पुतिन के अगले प्लान का खुलासा किया। दुगिन ने इशारों में कहा कि पुतिन कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। 2022 में मॉस्को के बाहरी इलाके में एक कार बम विस्फोट में उनकी बेटी की मौत हो गई थी।

कैलाश के पाला बदलने से राजनीति के केंद्र में आए जाट

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले नजफगढ़ इलाके के विधायक व दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने और आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने के बाद जाट बिरादरी के नेताओं की प्रासंगिकता और उनकी भूमिका को पुन: दिल्ली की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने उनके जाने के बाद जाट बिरादरी को अपने साथ रखने के लिए बीते सोमवार को नांगलोई से अपने जाट विधायक राघवेंद्र शौकीन को मंत्री बनाने का ऐलान किया है। तो वहीं, वर्ष 2008 में मटियाला से कांग्रेस के विधायक रहे सोमेश शौकीन को पार्टी में शामिल किया। पिछले कुछ वर्षों से भाजपा और उसका शीर्ष नेतृत्व जाट बिरादरी पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी, मगर अब इस समुदाय में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की राजनीति में वर्ष 1971 में जाट बिरादरी के नेताओं को महत्व मिलने की शुरूआत हुई थी। जाट समुदाय से बचने के लिए कैलाश गहलोत के जाने के बाद आप ने तेजी से कदम उठाते हुए नांगलोई से अपने जाट विधायक राघवेंद्र शौकीन को मंत्री पद देने की घोषणा की।

पांच सौ साल पहले एकजुट हुए होते, तो नहीं देखना पड़ता गुलामी का मुंह

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों से ज्यादा समय से रुका हुआ राम मंदिर निर्माण का काम सनातनियों की एकता के कारण महज दो वर्षों में पूरा हो गया और अगर देश500 साल पहले एकजुट होता तो उसे गुलामी का सामना नहीं करना पड़ता। आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में सुग्रीव किले के भव्य श्री राजगोपुरम द्वार का अनावरण किया। इस अवसर पर देशभर से आए साधु-संतों को संबोधित करते हुए उन्होंने अयोध्या में भव्य श्रीराममंदिर के निर्माण और सनातन धर्म की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, जो काम 500 सालों से रुका हुआ था, जिसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने बलिदान दिया, वो केवल सनातनियों के एकजुट होने मात्र पर प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी जी के नेतृत्व में दो वर्ष में ही पूरा हो गया। अगर 500 साल पहले हमने एकता दिखाई होती, तो गुलामी का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि 500 साल का लंबा इंतजार समाप्त हुआ है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रामलला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का सपना पूरा हुआ है।

लोक उत्सव से तंत्र का यंत्र बन गए हैं चुनाव

योगेन्द्र यादवस

इस साल चुनाव देखते-दिखाते, सुनते-बतियाते तथा लड़ते-लड़ाते हुए मुझे 40 बरस पूरे हो जाएंगे। मुझे याद है 1984-85 का वह अभूतपूर्व चुनाव, जिसमें राजीव गांधी की चुनावी आंधी ने सब भविष्यवाणियों को झुठला दिया था। उस चुनाव में प्रणय रॉय द्वारा इंडिया टुडे पत्रिका में किए विश्लेषण को पढ़कर मेरी चुनावी विश्लेषण और भविष्यवाणी में दिलचस्पी जगी थी।

पिछले चार दशकों में चुनावों के दौरान देश और दुनिया के अलग-अलग कोनों की धूल फांकने का मौका मिला, अखबार, टी.वी. और अब यूट्यूब पर विश्लेषण किया है, एक बार खुद चुनाव लडने और कई बार चुनाव लड़ाने का अवसर भी मिला है। जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है चुनाव का शाब्दिक और कानूनी चेहरा भले ही वही रहा है, लेकिन चुनाव नामक इस घटना का स्वरूप बुनियादी रूप से बदल गया है। मुझे याद है 1994 में जब मुझे जर्मनी के चुनाव देखने का मौका मिला, तब आंखों में चुभा था कि वहां सड़कों पर, बाजार में, होटल में और यहां तक कि अखबार के पन्नों पर भी कहीं चुनाव का कोई माहौल ही नहीं था। उन दिनों तक भारत के चुनाव एक मेले जैसे हुआ करते थे। दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, झंडियों की लडियां या फिर बड़े-बड़े झंडे। इनसे पूरा शहर पटा रहता था, चुनाव चल रहे हैं इसका आंख खोलने भर से पता रहता था।

पब्लिक को कुछ तकलीफ जरूर होती थी, जैसी हर त्यौहार में होती है। लेकिन कुल मिलाकर यह लोकोत्सव होता था, जिसमें रौनक थी, जनता के जनार्दन होने की खनक थी। अब चुनाव आयोग की तरफ से ही नाना प्रकार की बंदिशें लग गई हैं, सड़क से पोस्टर, बैनर, झंडियां लगभग गायब हो चुकी हैं। कभी अखबार में बड़ा विज्ञापन दिख जाता है, बस। चुनाव प्रचार घर की चारदीवारी के भीतर सिमट गए हैं, अक्सर केवल ड्राइंग रूम तक।

मेरे बचपन में ही चुनावी बुखार का पैमाना चुनावी रैलियां हुआ करती थीं। नेता आपकी पसंद की पार्टी का हो या नहीं, सारा शहर उसके भाषण को सुनने और उसकी रैली देखने जाया करता था। रैली में जुटी भीड़ और जनता की प्रतिक्रिया से ही चुनावी हवा का अनुमान लगाया जाता था। इस मायने में भी भारत का चुनाव यूरोप और अमरीका से बहुत अलग था, जहां नेता जनसंपर्क सिर्फ टी.वी. कैमरे के लिए करते थे। धीरे-धीरे हम भी उसी राह पर चल निकले हैं। चुनाव रैलियों से हटकर अब टी.वी. के पर्दे पर खिसक आया है। रैलियां अब भी होती हैं, लेकिन टी.वी. के लिए। अब चुनावी रैली में सामान्य मतदाता ईने-गिने ही होते हैं, चुनावी रैली अपने समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन का बहाना होती है। रैली में भी नेता जनता से बहुत दूर होते हैं।

सड़क और मैदान से ही खिसक चुनावी प्रचार आंगन और ड्राइंग रूम में चले आने से चुनाव की भाषा ज्यादा नफीस होनी चाहिए थी, खर्च घटना चाहिए था, लेकिन इसका ठीक उलटा हो रहा है। पहले गाली-गलौच, अनर्गल आरोप और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल विपक्षी दलों में भी बिल्कुल हाशिए पर खड़े नेता किया करते थे। पिछले 10 वर्षों में संवैधानिक पदों पर विराजमान नेताओं ने भी इस भाषा की मर्यादा को तोडने में अग्रणी भूमिका अख्तियार कर ली है। हर चुनाव में ही खर्चा दिन दोगुना, रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। पहले कभी-कभार ऐसा राजनीतिक कार्यकर्त्ता मिल जाता था, जो नाम मात्र के पैसे खर्च कर चुनाव जीत जाता था। अब ऐसे अपवाद ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा भले ही 40 लाख रुपए हो, लेकिन हर गंभीर उम्मीदवार औसतन 5-10 करोड़ रुपए खर्च करने पर मजबूर है। सम्पन्न राज्यों में यह राशि 25-30 करोड़ रुपए है तो कुछ शहरी सीटों पर 50 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक है। जरूरी नहीं कि लोग पैसा लेकर उसी उम्मीदवार को वोट डालेंगे लेकिन अब देश के अधिकांश इलाकों में वोटर भी चुनावी दक्षिणा को अपना अधिकार मानता है।

मीडिया कभी भी चुनाव में पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था, लेकिन आज की तरह सत्ता की गोदी में नहीं था, सत्तारूढ़ पार्टी के भोंपू का काम नहीं करता था, विपक्षी दलों और नेताओं का भेड़िए की तरह शिकार नहीं करता था। पहले चुनाव परिणाम टैस्ट मैच की तरह सुस्ताते हुए आते थे, अब ये भी टी-ट्वैंटी की रफ्तार से टी.वी. के पर्दे पर आते हैं। मोहक तस्वीरें व सुंदर ग्राफिक होते हैं, लेकिन सब कुछ बना-बनाया तयशुदा सा होता है। उस जमाने के चुनाव कार्यकर्त्ता जीतते और जिताते थे। वैसे आज भी उम्मीदवारों के चुनावी दफ्तरों में भीड़ दिखाई दे सकती है लेकिन दरअसल चुनाव जिताने का दारोमदार अब वहां से खिसक चुका है। लेकिन अब धीरे-धीरे कार्यकर्त्ता की जगह कंसल्टैंट आ रहे हैं। पार्टी कार्यालय का स्थान चुनाव मैनेजमैंट कंपनियों के हाई-फाई कार्यालय ले रहे हैं।

चुनाव की राजनीतिक स्ट्रैटेजी, उम्मीदवार से लेकर चुनावी थीम और नारे चुनने,चुनाव प्रचार सामग्री डिजाइन करने, नेता की छवि गढने और कार्यकर्त्ताओं की खरीद-फरोख्त करने का सारा ठेका अब चुनावी कंपनियां ले रही हैं। पहले नेता जनता को मोटिवेट करते थे, कार्यकर्त्ता जनता को मोबिलाइज करते थे, अब कंसल्टैंट जनता को मैनेज करते हैं।

एक जमाने में चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होते थे - एक जोखिम से भरा उत्सव, जिसमें जनता-जनार्दन नामक देवता कुछ भी वरदान दे सकता था, प्रसन्न न हो तो बड़े से बड़े को श्राप दे सकता था। अब चुनाव एक इवैंट है, जिसमें अधिकांश कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, नियोजित हैं, प्रायोजित हैं। चुनाव से लोक को पूरी तरह से बेदखल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन तंत्र ने लोक को चारदीवारी में कैद करने का यंत्र बना लिया है।

कोरिया के बैकुंठपुर में हाथियों का डेरा, एक साथ 11 हाथी मौजूद

■ वन विभाग की टीम मुस्तैद

कोरिया। कोरिया वन मंडल के सलक क्षेत्र में बीते पांच दिनों से हाथियों की मौजूदगी है। रात के समय में गजराज इलाके में खूब तांडव मचाते हैं। 11 हाथियों का दल यहां घूम रहा है। रात के समय में ये हाथी रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं और घरों में तोड़ फोड़ मचाते हैं। हाथियों के आतंक से लोगों में डर का माहौल है। गांव वाले रतजगा करने को मजबूर हैं।

हाथियों के दस्तक के बीच वन विभाग की टीम इलाके में मुस्तैद हो गई है। वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी रातभर क्षेत्र का दौरा करते हैं। वे गांव वालों को सुरक्षा और समझाइश दे रहे हैं। सलवा, मेंको, परचा बस्ती जैसे प्रभावित गांवों में वन मंडल के डीएफओ प्रभाकर खलखो और एसडीओ अखिलेश मिश्रा लगातार दौरा कर रहे हैं। मंगलवार की रात को भी दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की खैरियत पूछी।

वन विभाग की टीम ग्रामीणों को अलर्ट कर रही है। उन्होंने हाथियों के मूवमेंट की जानकारी गांववालों को दी। इस दौरान बिजली विभाग के जेई चंद्रा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने फील्ड कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि ग्रामीणों को हाथियों के मूवमेंट की जानकारी तुरंत दी जाए। जिसके बाद इलाके में वन विभाग की टीम और मुस्तैद हुई।

एसडीओ अखिलेश मिश्रा ने कहा वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के उपाय बता रही है। हाथियों की पसंद बना कांदा बारी का जंगल हाथियों की पसंद बन चुका है। हर साल हाथियों का दल यहां आकर डेरा डालता है। बीते 15 साल से इस क्षेत्र में हाथियों के मूवमेंट रहा है। यहां का घना और सुरक्षित जंगल हाथियों के रहने के लिए आदर्श माना जाता है। हाथियों के इस इलाके में मौजूद रहने से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। किसानों को अपनी फसल की चिंता सता रही है। रात के समय में वन विभाग के आने से गांव वालों को सेफ्टी की आस जगी है।

कबीरधाम के एमपी-सीजी बॉर्डर पर पधारे गजराज, जंगल में मौजूद है चार हाथी

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के एमपी-सीजी बॉर्डर पर एक बार फिर से हाथी पहुंच गए है। आज बुधवार सुबह तक इनकी लोकेशन एमपी के गोपालपुर के आसपास मिली है। ये कभी एमपी के क्षेत्र में जाते है तो कभी सीजी में आ जाते हैं। ये लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं।

फिलहाल जंगल में चार हाथी मौजूद हैं। बॉर्डर में हाथी की उपस्थिति के बाद वन विभाग हाई अलर्ट पर है। बीते तीन दिन सोमवार से आज बुधवार को जंगल में वन विभाग की टीम रतजगा कर रही है। मंगलवार को हाथियों का लोकेशन कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत वनांचल क्षेत्र तेलियापानी लेदरा के आसपास थी। यह गांव एमपी-सीजी से लगा हुआ है।

यहां वन विभाग की टीम पहुंची हुई थी। यह बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। हाथियों के धमक से इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं, ताकि हाथियों का दल हमला करें तो कोई जनहानि ना हो। बताया जा रहा है कि ये हाथी पिछले एक महीने से कबीरधाम जिला से लगे एमपी के करंजिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत चमकी के जंगल में डेरा जमाए हुए थे। सोमवार को मध्यप्रदेश वन विभाग की तरफ से हाथियों को खदेड़ा गया तो हाथियों का दल छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पहुंच गया है।

इस दौरान हाथियों का दल जिस रास्ते से पहुंचा, उस रास्ते में पड़ने वाले खेत में लगी कोदो, कुटकी, ज्वार की फसल को रौंद दिया है। भोजन की तलाश में हाथी जिले के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

हाथी शावक की मौत का वन विभाग ने किया खुलासा

रायगढ़। रायगढ़ जिले में दो दिन पहले धरमजयगढ़ वन मंडल के जंगलो में हाथी शावक के एक माह पुराने कंकाल मिलने के मामले का वन विभाग ने खुलासा कर दिया है। जंगल में विचरण के दौरान नुकीले लकड़ी के ठूंठ में गिर जाने से हाथी शावक की मौत हुई थी। वन विभाग की टीम अब इस मामले मे जांच उपरांत लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई करने वाली है।

इस संबंध में वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बोरो रेंज में 17 नवंबर को रुवांफूल परिसर के कक्ष क्रमांक 667 आर.एफ। प्रधानझरिया नामक स्थल में जंगली हाथी शावक के शव मिलने की जानकारी परिसर रक्षक ने वन परिक्षेत्राधिकारी को दिया था। जिसके तत्पश्चात वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने अधिनस्थ वन कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे।

विभागीय टीम को जंगल के अंदर एक मृत नवजात हाथी के अवशेष मिले तथा आस-पास हाथी के दल का विचरण के निशान व जगह-जगह लीद पाये गये। परिक्षेत्र अतंर्गत उक्त कक्ष क्रमांक एवं आस पास में 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक हाथियों का दल का विचरण था, जिसकी सतत निगरानी की जा रही थी। जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रात्रि होने के कारण मौका स्थल में पड़े अवशेष को सुरक्षित निगरानी में वन परिक्षेत्राधिकारी बोरो द्वारा रखा गया। 18 नवंबर को धरमजयगढ़ वनमंडल एवं उप वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ की उपस्थिति में पशु चिकित्साधिकारीयों की गठित जिला स्तरीय टीम के सदस्यों ने मौके पर उपस्थित होकर मृत नवजात हाथी के अवशेष का जांच किया गया। मृत हाथी (नवजात) के अवशेष जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट द्वारा यह बताया गया कि प्रथम दृष्टया हाथी (नवजात) की मृत्यु दल के साथ विचरण के दौरान नुकीले ठूंठ में गिरने के कारण हुई है। जांच उपरांत मृत नवजात हाथी के अस्थी (बोन) एवं मल (फीकल) का सेम्पल अग्रिम जांच के लिए सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् जगंल में सुखी लकड़ी सग्रहण कर हाथी (नवजात)के अवशेष को पंचों के समक्ष विधिवत् मृत नवजात हाथी के अवशेष का दहन किया गया।

डबल इंजन की सरकार में न फंड की कमी न विकास कार्यों में देरी: उद्योग मंत्री

कोरबा शहर के विभिन्न वार्डों में 38 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन

कोरबा। वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने मंगलवार को कोरबा नगर में विभिन्न वार्डों में 38 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। वार्ड क्रमांक 55 बलगी में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन की मुख्य आतिथ्य में दशहरा मैदान दुर्गा पंडाल के पास यादव समाज के मांग अनुरूप सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य लागत 10 लाख रुपए और वार्ड क्रमांक 01 सर्वमंगला पारा शिव मंदिर के पास सांस्कृतिक मंच का निर्माण कार्य लागत 5 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्य का भूमिपूजन संपन्न हुआ।

इसी तरह तुलसीनगर वॉर्ड क्रमांक 02 में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 02 हनुमान मंदिर के सामने शेड निर्माण कार्य 8 लाख, वार्ड क्रमांक 32 रामपुर हाउसिंग बोर्ड कालोनी में सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य लागत 5 लाख, वार्ड क्रमांक 12 रेलवे कॉलोनी न्यू अमरैया पारा शिव मंदिर के पास निर्मित मंच का बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य 5 लाख, वार्ड क्रमांक 29 शिवनगर पोड़ीबहार में गुरु दयाल मानिकपुरी के घर के पास सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य 5 लाख के कार्यों की नींव रखी गई। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जिन कार्यों की आधारशिला रखी जा रही है, इन कार्यों की मांग गणेश पूजा और अन्य कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोगों ने की थी।

मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जनता की जरुरत और उनकी मांग को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति दी जा रही है और इसी का नतीजा है कि एक से डेढ़ महीने के भीतर ही इन कार्यों की शुरूआत भी हो रही है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य अब कोरबा शहर में तेज़ी से होने लगा है। बड़े निर्माण कार्यों के साथ वार्डों के छोटे छोटे कार्य भी तेजी से होने लगे हैं।

नशीला ओनेरेक्स सिरप खपाने की फिराक में घुम रहे दो युवक गिरफ्तार

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की पुलिस ने नशीली ओनेरेक्स सिरप खपाने की फिराक में घुम रहे दो युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 70 बोतल नशीली ओनेरेक्स सिरप जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। उक्त मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के मुताबिक लैलूंगा पुलिस ने खम्हार पुलिया पर नाकेबंदी कर 70 बोतल नशीली ओनेरेक्स सिरप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह सिरप नशे के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, और आरोपी इसे अवैध बिक्री के लिए तस्करी कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के अवैध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। लैलूंगा थाना प्रभारी राजेश जांगड़े को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तारागढ़ का आरीफ खान और उसका साथी मोटरसाइकिल से ग्राम लुडेग से लैलूंगा की ओर नशीली सिरप लेकर आ रहे हैं। जिसके बाद पुलिस टीम को नाकेबंदी के लिए रवाना किया गया। इस दौरान खम्हार पुलिया पर बाईक क्रमांक सीजी 13 एजेड के चालक को रोककर जब उनके थैलों की तलाशी ली गई तो उनके थैलों से प्लास्टिक बोरी में 70 बोतल ओनेरेक्स सिरप बरामद हुआ।

आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम आरीफ खान 21 वर्ष निवासी तारागढ़ और हर्षित अग्रवाल 26 वर्ष निवासी लुडेग, जिला जशपुर बताए। दोनों ने सिरप को अवैध बिक्री के लिए ले जाने की बात स्वीकार की। जब्त सामान में 70 बोतल सिरप कीमत 12 हजार 600 सौ और बजाज मोटरसाइकिल कीमत 30 हजार शामिल है। दोनों को मिलाकर कुल 42 हजार 600 की बरामदगी की है। लैलूंगा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना लैलूंगा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

जमीन का बनाया फर्जी दस्तावेज

कलेक्टर ने नगर सैनिक, शिक्षा विभाग के क्लर्क सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश

बलरामपुर-रामानुजगंज। जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर पटवारी पर चौहद्दी बनाने का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है। मामले में जिला स्तरीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कुल 11 व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई, जिसमें नगर सैनिक और शिक्षा विभाग में क्लर्क सहित 10 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया गया है।

कलेक्टर कार्यालय की ओर से राजपुर एसडीएम को भेजे पत्र के अनुसार, अनुभाग राजपुर के ग्राम मदनेश्वरपुर, प0ह0नं0 27 की पटवारी अनिमा पैकरा द्वारा खसरा नंबर 544/22 रकबा 2.371 तथा खसरा नंबर 550/1 के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 के अवलोकन के लिए जिला अभिलेखागार को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मिलान उपरांत उपरोक्त अभिलेख के फर्जी होने की बात सामने आई।

अधिकार अभिलेख के अवलोकन उपरांत पटवारी अनिमा पैकरा ने कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया कि व्हाट्सअप के जरिए ग्राम मदनेश्वरपुर का अधिकार अभिलेख 1954-55 का नकल प्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर जमीन की खरीदी के लिए चौहद्दी बनाये के लिए बोला। अवलोकन में नकल संदेहास्पद पाए जाने पर पटवारी ने चौहद्दी बनाने से मना कर दिया।

इसके बाद चौहद्दी बनाने के लिए सौरभ सिंह, राजेश सिंह और रविदास फोन कर दबाव बनाने लगे। इस बात की जानकारी पटवारी ने राजपुर एसडीएम को दी, जिसके बाद राजपुर एसडीएम ने अभिलेख जांच / खसरा मिलान के लिए जिला अभिलेखागार भेजा गया। जांच में शिकायत सही पाए जाने और कूटरचित फर्जी नकल तैयार किए की पुष्टि होने पर दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का दिया गया निर्देश

सुनील मिंज पिता स्व। शम्भू मिंज, निवासी लेजुआपोखरा, बलरामपुर। सौरभ सिंह पिता फलेन्दर सिंह, निवासी मेन रोड पोस्ट ऑफिस के पास राजपुर। राजेश सिंह, ठेकेदार, निवासी ग्राम बलरामपुर।बसील खलखो पिता कार्लस जालक्सो, निवासी ग्राम भेलईखुर्द, तहसील राजपुर। रमेश ठाकुर पिता बबन ठाकुर, निवासी गोधनपुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा। रामरूप यादव पिता सोनई, निवासी ग्राम मदनेश्वरपुर, तह0 राजपुर। सुरेशचंद्र मिश्र पिता स्व. सिद्धेश्वर मिश्र, निवासी ग्राम डूमरसोता, पो0 कांडी, प्रखण्ड- गढ़वा, जिला गढ़वा, झारखण्ड। जयप्रकाश श्रीवास्तव पिता सुरेश लाल श्रीवास्तव, निवासी ग्राम राजमोहिनी देवी वार्ड अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0। तेरेसा लकड़ा पति सुनील मिंज, नगर सैनिक, जिला सेनानी बलरामपुर। विजय बहादुर सिंह, सहा0ग्रेड-03, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पीजी कॉलेज में 50 लाख रुपये की गड़बड़ी, प्राचार्य सस्पेंड

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज में 50 लाख रुपये के गड़बड़ी मामले में राज्य सरकार ने प्रभारी प्राचार्य डॉ. बीएस चौहान को सस्पेंड कर दिया है। यह मामला कॉलेज के जनभागीदारी समिति से जुड़ा है। इस मामले को लेकर बीते 11 नवंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग किया। एबीवीपी नेता तुषार कुमार ने बताया कि हाल में ही कॉलेज के जनभागीदारी शुल्क की राशि 50 लाख से अधिक का गबन का मामला सामने आया है। इससे कॉलेज को नुकसान हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाए। मामले में राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए सस्पेंड कर दिया है। उन्हें दुर्ग में अटैच किया गया है। बता दें कि इस मामले में प्राचार्य का कहना था कि जनभागीदारी शाखा का कामकाज देख रहे क्लर्क प्रमोद वर्मा ने यह गड़बड़ी की है। क्लर्क को दो बार नोटिस भी दिया जा चुका है। अक्तूबर माह में ये गड़बड़ी हुई है।

भूमि दाता का नाम अंकित करने हाईकोर्ट ने दिया आदेश

बिलासपुर। जैन तीर्थ बाकेला (पंडरिया) के मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भूमि दाता स्वर्गीय गौतम चंद लोढ़ा का नाम इस तीर्थ में अंकित करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिका को खारिज करते हुए मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न करने का आदेश दिया गया है। स्वर्गीय गौतम चंद जैन ने आचार्य श्री मनोज सागर की प्रेरणा से पंडरिया ब्लॉक के बाकेला में 13 एकड़ 56 डिसमिल भूमि खरीदकर एक ट्रस्ट का गठन किया था और इस भूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया था। मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा था कि उनका निधन हो गया। इस बीच, मुंगेली स्थित एक अन्य जैन ट्रस्ट ने इस भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लिया। इसके साथ ही, ट्रस्ट के अनूप चंद बैद ने अपनी ओर से इस स्थान पर मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। इस पर स्वर्गीय गौतम जैन के पुत्र मनीष जैन ने इस मामले को संभागायुक्त दुर्ग से लेकर हाई कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई लड़ी।

सेवा सहकारी समितियों में नियुक्ति की फर्जी लिस्ट वायरल

बालोद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन दिनों जिले के 122 सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त किए गए अध्यक्ष, सभापति और प्रभारियों की सूची वायरल हो रही है। इस फर्जी वायरल सूची के झांसे में आए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज डौंडी ब्लॉक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर समितियों में गैर आदिवासियों को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है। वायरल सूची का विरोध जताते हुए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज डौंडी ब्लॉक की ओर से कलेक्टर को पत्र लिख पत्र में इन नियुक्तियों को सवाल उठाते हुए इसे नियम विरुद्ध बताते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति करने की मांग की है। वहीं सहकारिता विभाग के उप पंजीयक राजेंद्र राठिया ने सूची को पूरी तरह भ्रामक और फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया कि एक-दो दिनों में लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

सड़क हादसे में घायल किसान ने अस्पताल में तोड़ा दम

जगदलपुर। जगदलपुर के करपावंड थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदगाव निवासी किसान साप्ताहिक बाजार में खरीददारी जाने के दौरान अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। घटना में घायल किसान को मेकाज में भर्ती किया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि करपावंड थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदगाव निवासी सुखराम बघेल पिता दासों 45 वर्ष 14 नवंबर की सुबह अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर घर से साप्ताहिक बाजार करपावंड जाने के लिए निकला, जहां चिऊरगांव के पास एक अज्ञात वाहन ने सुखराम की मोटरसाइकिल को ठोकर मार फरार हो गया। आसपास के लोगों के साथ ही घरवाले घायल को बकावंड के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ उसे बेहतर उपचार के लिए मेकाज भेजा गया। चार दिनों तक चले उपचार के बाद किसान ने दम तोड़ दिया। जगदलपुर में टॉयलेट बनाने के दौरान सुबह से ही राजमिस्त्री के सीने में दर्द हो रहा था खाना खाने के बाद राजमिस्त्री सो गया काफी देर तक नहीं उठने के बाद उसे स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया।

हार्डवेयर की दुकान से 80 हजार की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

रायगढ़। रायगढ़ जिले में अज्ञात चोरों ने छत के जरिये हार्डवेयर दुकान में घुसकर काउंटर का ताला तोड़ते हुए 80 हजार रूपये नगदी रकम की चोरी कर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। उक्त मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेन्ड्रा निवासी आकाश गुप्ता 27 साल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका गुप्ता हार्ड वेयर दुकान और घर एक ही बिल्डिंग में है। जहां 17 नवंबर की रात 9 बजे वह दुकान बंद करके घर चला गया था। अगले दिन सुबह 6 बजे उसके पिता जब दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान के काउंटर का ताला टूटा हुआ था और गल्ले में रखे नगदी रकम 80 हजार रूपये की चोरी हो चुकी थी। जिसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। बहरहाल घरघोड़ा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।

नायब तहसीलदार से थाना प्रभारी के विवाद पर लामबंद हुए प्रशासनिक अधिकारी

बिलासपुर। बिलासपुर में नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा और सरकंडा थाना में थाना प्रभारी तोपसिंग नवरंग और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद के बाद प्रशासनिक अधिकारी लामबंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ एवं राज्य प्रशासनिक सेवा संघ आज कलमबंद कर सरकंडा थाना के सामने विरोध-प्रदर्शन करेंगे। यह भी पढ़ें = सुरक्षाबलों के अभियान से दहशत में नक्सली, बैनर लगाकर जवानों से की यह अपील

मंगलवार को सरकंडा थाना में थाना प्रभारी तोपसिंग नवरंग और पुलिसकर्मियों से विवाद के बाद नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा ने थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं, पुलिस ने भी नायब तहसीलदार और उनके भाई पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और गाली-गलौज का मामला दर्ज किया है।

मामले में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ एवं राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से सभी कलेक्टर को मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। इसमें प्रारंभिक स्तर पर किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिए जाने और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी स्तर की जाँच कमिटी गठित नहीं किए जाने पर क्षोभ जताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के वारंट का झांसा देकर लाखों की ठगी

■ 5 दिनों तक ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट

दुर्ग। सायबर ठग किस तरह से पढ़े लिखे लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं।इसकी बानगी दुर्ग में देखने को मिली। जहां साइबर ठगों ने 49 लाख रुपए की ठगी की है। इस बार ठगों ने प्रार्थी को डिजिटल अरेस्ट किया।इस दौरान प्रार्थी करीब 5 दिनों तक ठगों के संपर्क में रहा।ठगों ने उसे भरोसा दिलाया कि यदि उसने उनकी बात नहीं मानी तो बड़ी कार्रवाई होगी।आखिरकार अपने झांसे में लेकर ठगों ने 49 लाख रुपए उड़ा दिए।जिसकी शिकायत प्रार्थी ने पुलिस से की है।

भिलाई में रहने वाले प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रकाश कश्यप के साथ 49 लाख की ठगी हुई है।जिसकी सूचना पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। प्रार्थी की कंपनी पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में स्थित है। 7 नवंबर को इंद्रप्रकाश कश्यप खड़कपुर के पश्चिम बंगाल में थे। तभी अचानक एक अनजान नंबर से उनके पास फोन कॉल आया। फोन पर बात करने वाले ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया। सामने वाले ने इंद्रप्रकाश से कहा कि उनके आधार कार्ड से 29 लोगों ने सिम जारी करवाए हैं।इसके बाद उन नंबरों से आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए हैं।

इसके बाद ठगों ने मुंबई के कथित साइबर ब्रांच के अधिकारी को फोन ट्रांसफर किया। पीड़ित इंद्रप्रकाश कश्यप को साइबर ब्रांच के अधिकारी ने कहा कि उनके आधार कार्ड से मलाड मुंबई के केनरा बैंक में खाता खोला गया है। उस खाते से करोड़ों का लेनदेन किया गया है।

इसमें जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खाते से भी लेनदेन होने का सबूत मिला है। जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

इसके बाद आरोपियों ने फायदा उठाकर जांच होने तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। आरोपी दिए गए समय पर वीडियो कॉल कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। फिर आरोपियों ने कहा कि वह सीक्रेट्स सुपरविजन अकाउंट खोल रहे हैं। जिसमें उन्होंने सभी खातों के जमा रुपए का ट्रांसफर करना होगा। जिसे दो दिन बाद वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद आरोपियों के कहे अनुसार पीड़ित ने 49 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब इंद्रप्रकाश कश्यप को यह बात समझ आई तो उसने तत्काल पुलिस को लिखित में सूचना दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में जुट गई ,तो वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है।

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया 7 से 11 तारीख के बीच प्रार्थी को डिजिटल अरेस्ट करके 49 लाख रुपए की ठगी की गई है।उस वक्त प्रार्थी वेस्ट बंगाल में थे।जब ये 11 तारीख को वापस आए तो उनको फिर से फोन कॉल करके धमकाया गया।इसके बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ।जिसके बाद भिलाई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

वहीं इस पूरे मामले में साइबर एक्सपर्ट संकल्प राय ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक नया प्रकार का साइबर अपराध है। साइबर ठग खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को विश्वास दिलाता है कि अपराध किया है। उन्हें डिजिटल गिरफ्तार कर लेता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसी फेक कॉल्स पर कभी भी आप विश्वास ना करें, ऐसा कॉल आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए।

संक्षिप्त समाचार

सीएम साय दिल्ली रवाना, राज्य सांस्कृतिक दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली के भरतमंडपम में छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले सीएम साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को अच्छी सफलता मिल रही है। दोनों जगह भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने बताया कि शाम साढ़े पांच बजे से साढ़े सात बजे तक एम्फी थियेटर-1 भरतमंडपम में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सांस्कृतिक दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 21 नवंबर को दोपहर 1.45 बजे नियमित विमान से रायपुर लौट आएंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में छत्तीसगढ़ राज्य की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार और प्रदर्शन के लिए कुल 11 स्टाल लगाए गए हैं, जहां विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की अवधारणा पर छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाथकरघा, हस्तशिल्प, हर्बल एवं कृषि विभाग के प्रदर्शन स्टाल लगे हैं।

छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री साय ने की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। यह फिल्म तात्कालिक सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है, जो झूठे नरेटिव फैलाकर सत्य को दबाने का निंदित प्रयास करती थी। फिल्म दर्दनाक घटना को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि द साबरमती रिपोर्ट फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने का प्रयास किया गया था।

महाराष्ट्र बिटकॉइन मामला : लिंक सामने आने पर ईडी ने की बड़ी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले से जुड़े होने के बाद ईडी ने गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को गौरव मेहता के छत्तीसगढ़ ठिकानों पर छापेमारी की, जो कथित तौर पर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में बिटकॉइन लेनदेन मामले से जुड़े हैं। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के तहत की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेहता के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। भाजपा ने एनसीपी नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर मौजूदा चुनावों में अवैध रूप से बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, क्योंकि उसके नेताओं ने कथित तौर पर एक रिकॉर्डिंग चलाई है, जिसमें दावा किया गया है कि यह सुले की आवाज है। मेहता कथित तौर पर इन लेनदेन से जुड़े हैं। सांसद सुले ने आरोपों से इनकार किया है। सूत्रों के अनुसार, ईडी मेहता और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने भोले-भाले लोगों से बिटकॉइन के रूप में बड़ी रकम (2017 में छह हजार 600 करोड़ रुपये) इकट्ठा की और बिटकॉइन के रूप में 10 प्रतिशत प्रति माह रिटर्न का झूठा वादा किया। यह मामला महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज पुलिस एफआईआर से जुड़ा है।

छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष बने अजय तिवारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ (छत्तीसगढ़) के सदस्यों की एक आमसभा हुई जिसमें प्रदेश भर के सदस्य उपस्थित रहे। आमसभा में विभिन्न पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन भी हुआ जिसमें अध्यक्ष अजय तिवारी(रायपुर) व अन्य पदाधिकारी चुने गए। संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के मुताबिक-श्री अजय तिवारी अध्यक्ष, रायपुर, श्री कुंजबिहारी मिश्रा उपाध्यक्ष, बिलासपुर श्री बी.सिद्दीकी महामंत्री, रायपुर, श्री अमित दास सह-मंत्री जगदलपुर,श्री जीवराखन लाल देवागन, कोषाध्यक्ष,छुरी कोरबा चुने गए। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य में श्री प्रशांत कुमार घोष, धमतरी,श्री बद्रीप्रसाद बॉम्बी, बस्तर,डॉ. जया द्विवेदी, रायगढ़,श्री नरेन्द्र जाधव, तिल्दा-रायपुर का नाम तय हुआ। आमसभा में सभी ने संस्था की बेहतरी के लिए काम करने का संकल्प लिया।

मछली नदी में सिंचाई के लिए बनेगा स्टापडेम

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सरगुजा जिले के विकासखंड लुण्ड्रा के करौली गांव में मछली नदी पर सिंचाई के लिए स्टापडेम सह पुलिया निर्माण कार्य हेतु चार करोड़ 85 लाख 23 हजार रूपए स्वीकृत किए है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर क्षेत्र के लोगों को निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन, सोलर संयंत्र तथा पाईप डिस्ट्रीव्यूसन की नेटवर्क के जरिए 180 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से योजना का निर्माण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है।

रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जल्द

बिहार-झारखंड के साथ अब सिंगापुर-दुबई से भी जुड़ेगा छत्तीसगढ़, उड्डयन मंत्री ने दिया ये भरोसा

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास को लेकर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने पर हरी झंडी मिली।

राज्य के मुख्यमंत्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर यात्री ट्रैफिक काफी अच्छा है, जिससे ये सेवाएं व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित होंगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।

सीएम साय ने राज्य में वर्तमान में कोई बड़ा कार्गो सुविधा केंद्र नहीं होने की जानकारी देते हुए रायपुर के एयरपोर्ट को एक केंद्रीय कार्गो हब में विकसित करने का प्रस्ताव दिया।

उन्होंने कहा कि इससे कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैठक में बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए 3ष्ट ढ्डस्नक्र कैटेगरी में अपग्रेडेशन का प्रस्ताव भी रखा है। मुख्यमंत्री साय ने इसके लिए रेडियो नेविगेशन सिस्टम डीवीओआर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय मंत्री ने बिलासपुर एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट लैंडिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसे तुरंत शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट को रायपुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा क्षेत्र की सांस्कृतिक और खनिज संपदा को देखते हुए नई उड़ान सेवा शुरू करने से लोगों को काफी लाभ होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट्स पर आरसीएस उड़ानों के लिए वित्तीय सहायता को बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि इन रूट्स पर कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी। साय ने बताया कि जगदलपुर से रायपुर के बीच इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ान सेवा को कम यात्रियों के चलते बंद कर दिया गया था। इसे पुनः सही समय पर शुरू करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस मार्ग पर हवाई कनेक्टिविटी की भारी मांग है। केंद्रीय मंत्री ने अन्य प्रस्तावों पर भी सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले सीएम साय

रायपुर/ नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम साय ने कहा, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ में चल रही नक्सली गतिविधियों से अवगत कराया। उनके मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार में हम तेजी से नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। हमारी सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। सुरक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार ने एंटी-नक्सल ऑपरेशन में

बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 11 महीने में लगभग 200 नक्सली मारे गए हैं, वहीं 700 से अधिक नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प की दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया केंद्र सरकार राज्य में सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है।

अपराध का गढ़ बन गया है रायपुर, अपराधियों को मिल रहा संरक्षण: विकास

- **राजेश मूणत बोले- आरोपियों को मिलेगी सजा**

रायपुर। राजधानी में लगातार अपराध बढ़ रहे। बीते 24 घंटे में तीन हत्याएं हुई है। बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा ने रायपुर को अपराध का गढ़ बना दिया है। महिला-बहनें शहर में सुरक्षित नहीं है। अपराधी अपराध करते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, कोई ना कोई संरक्षण दे रहा होगा। वहीं भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

सीजीपीएससी मामले में टामन सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में विकास उपाध्याय ने कहा, सीएसआर मद से 45 लाख रुपए एनजीओ में भेजने का जिक्र प्रेस नोट में हुआ है। जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा 15 साल में 14 सीट पर सिमट कर रह गए थे। अगर किसी ने

गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में किस व्यवस्था में पैसा डाला गया, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई गलत काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

धान खरीदी के बीच में राइस मिलर्स असहयोग आंदोलन कर रहे। इस पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, पिछले 5 साल में राइस मिलों को इतना फायदा पहुंचा कि कई राइस मील खुल गए। बीजेपी की नीति और सोच किसानों को परेशान करने वाली है। जब राइस मिल वाला परेशान होगा तो किसान भी परेशान होगा। पिछले 5 साल राइस मिल वालों को इतनी पर्याप्त मात्रा में धान मिलता था कि वह उसका मिलिंग करते थे। बीजेपी की सोची समझी साजिश है। सरकार जानबूझकर उनका पेमेंट नहीं कर रही है।

मुख्यमंत्री के ईवीएम वाले बयान पर विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, ईवीएम पर सवालिया निशान पूरे देश में है। अभी जो रीसेंट में चुनाव हुआ था पूरे देश का सबसे बड़ा चुनाव हुआ था। उस पर भी लोगों ने सवाल उठाया। जहां संदेह होगा वहां पर लोग कहेंगे। मशीन को लेकर लोगों में संदेह है। सामान्य आदमी से आप पूछोगे तो मशीन पर संदेह की बात करेगा। अगर संदेह होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगी।

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई : मूणत

राजधानी में लगातार हो रहे अपराध को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि पुलिस के जूते का वजन दिखना चाहिए। साय सरकार का सख्त आदेश है। कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, उनके खिलाफ शासन सख्त कार्रवाई करेगा।

महाराष्ट्र और झारखंड में बन रही भाजपा की सरकार: साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों जगह भाजपा को, एनडीए को अच्छी सफलता मिल रही है। दोनों जगह भाजपा की सरकार बन रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कांग्रेस के चुनाव परिणाम को लेकर ईवीएम को दोष पर कहा कि यह लोग कई बात यह बात बोल चुके हैं। हारते हैं तो पूरा दोष ईवीएम को देते हैं, और जीतते हैं, तो उनके लिए सब सही हो जाता है। दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर सीएम साय ने बताया कि आज दिल्ली में भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ दिवस है। यहां प्रत्येक दिन हर एक राज्य का दिवस मनाया जा रहा है। गवर्नर के आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा।

श्रीमान नोटरी पब्लिक, जिला बेमेतरा, छ.ग.

शपथ पत्र

मैं राजकुमार पटेल, उम्र लगभग 48 वर्ष, आ. श्री नारद सिंह पटेल, जाति लोधी, निवासी ग्राम बगलेडी. पो. केशतरा, तहसील साजा व जिला बेमेतरा, छ.ग. का हूं जो कि निम्न कथन शपथपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि:

1. यह कि मेरा नाम व पता उपरोक्तानुसार है।
2. यह कि मेरा नाम मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक, राजकुमार पटेल अंकित है जो कि मेरा प्रचलित नाम है। जबकि मेरे द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम भाटापारा से लिये गये पालिसी न. 358003521 में मेरा नाम त्रुटिवश राजेन्द्र कुमार उर्फ राजीव अंकित हो गया है। मैं केवल अपने प्रचलित नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूं।
3. यह कि राजकुमार पटेल एवं त्रुटिवाला नाम राजेन्द्र कुमार उर्फ राजीव दोनों नाम एक ही व्यक्ति के लिए अर्थात मेरे लिए ही प्रयुक्त किया गया नाम है।
4. यह कि इसके चलते मुझे भविष्य में कोई परेशानी न हो मैं कंडिका 2 अनुसार लिये गये पालिसी न. 358003521 में अपना प्रचलित नाम राजकुमार पटेल आ. नारद सिंह पटेल, दर्ज कराना चाहता हूं। यदि मेरे नाम को लेकर भविष्य में कोई परेशानी आती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे स्वयं की होगी ।
5. यह कि मेरे द्वारा न ही असत्य कथन किया गया है और न ही सत्य कथन को छिपाने का प्रयास किया गया है। अतः तदाशय के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

राजकुमार पटेल शपथकर्ता

//सत्यापन//

मैं राजकुमार पटेल, उम्र लगभग 48 वर्ष, आ. श्री नारद सिंह पटेल, जाति लोधी, निवासी ग्राम बगलेडी, पो. केशतरा, तहसील साजा व जिला बेमेतरा, छ.ग. का सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र की कंडिका क्रं. 1 से लेकर 5 तक की जानकारी मेरे जानकारी में सत्य एवं सही है। अतः आज दिनांक 18.11.2024 को शपथ पत्र लिखाकर, पढ़कर समझकर तथा स्वीकार किये जाने पर मुकाम बेमेतरा में सत्यापित कर अपना हस्ताक्षर कर दिया।

राजकुमार पटेल
सत्यापनकर्ता

छत्तीसगढ़ ने मत्स्य पालन में फिर लहराया परचम

कांकेर जिले को मिलेगा बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, अवार्ड के लिए चयन होने पर सीएम ने जताई खुशी

रायपुर। छत्तीसगढ़ ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। कांकेर जिले को यह राष्ट्रीय अवार्ड 21 नवंबर विश्व मात्स्यिकीय दिवस के अवसर पर मिलेगा। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह यह सम्मान को प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिले को देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चयन होने पर प्रसन्नता जताई। सीएम साय ने इस उपलब्धि के लिए कांकेर जिला प्रशासन सहित राज्य के सभी मत्स्य किसानों और मछलीपालन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है।

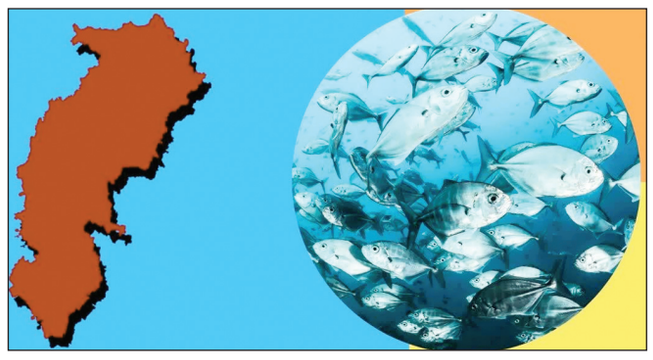

विष्णु देव साय ने कहा छत्तीसगढ़ लैंड लॉक प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्य पालन के

क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर हैं। यह उपलब्धि हमारे राज्य के मत्स्य कृषकों की मेहनत का परिणाम है। छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन के मामले में न सिर्फ पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी मछली बीज निर्यात कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कुल 1,29,039 जल स्त्रोत मौजूद हैं, जिसमें जल क्षेत्र 2.1032 लाख हेक्टेयर है। इनमें से 96 प्रतिशत जल क्षेत्र में किसी न किसी तरह से मत्स्य पालन किया जा रहा है। राज्य में 3571 किमी का नदीय जल क्षेत्र भी मौजूद है। इसके साथ ही अधिक मत्स्य पालन करने के लिए अन्य जलक्षेत्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। अब तक कुल 6783 हेक्टर जलक्षेत्र बनाया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ राज्य एक समय मत्स्य बीज के लिए पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों पर निर्भर था। लेकिन अब प्रदेश में कुल 82 नए हैचरी बनाकर 115 हैचरियों के जरिए 546 करोड़ मत्स्य बीज हर साल उत्पादन किया जा रहा है। इससे मत्स्य बीज के मामले में छत्तीसगढ़ न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि अन्य राज्यों को भी मत्स्य बीज निर्यात कर रहा है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हर साल 7.130 लाख टन मछली उत्पादन हो रहा है। अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 8वें स्थान पर है। इसके अलावा अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन के लिए जलाशयों और बंद खदानों में अब तक 9551 केज, 415 बायोफ्लॉक, 6 आरएएस और 253 बॉयोफलॉक पॉण्ड स्थापित किए गए हैं।

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जांजगीर में थोक मछली बाजार बनाए गए हैं। प्रदेश के मत्स्य पालकों का एनएफडीपी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। प्रदेश के मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक से लोन की सुविधा भी दी जा रही है। पात्र होने पर मछला पालकों को एक प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत ब्याज पर शार्ट टर्म लोन भी दिया जा रहा है।

रायपुर में होगी सीडी कांड की सुनवाई

राजेश मूणत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना

रायपुर। कथित सेक्स सीडी कांड में सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में दीगर राज्य में सुनवाई करने के आवेदन को वापस लेने के साथ राज्य में सुनवाई होने का रास्ता खुल गया है। इस पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि डर के कारण सीबीआई को प्रतिबंधित किया था।

पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले सीबीआई को प्रतिबंधित किया था। मामले में चालान पेश होने वाला था, उससे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। हमने कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसके बाद यहां पर सुनवाई होगी।

वहीं मामले में पूर्व विधायक

विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गोलमोल करके इस पूरे प्रकरण को पेचीदा किया है। आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। क्या-क्या कारण हैं, स्पष्ट होगा। किस प्रकार से केस वापस किया गया है, यह भी स्पष्ट हो जाएगा।

बता दें कि सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर सेक्स सीडी कांड की सुनवाई दीगर राज्य में करने का आवेदन वापस ले लिया था। सीडी कांड 27 अक्टूबर 2017 को उजागर हुआ था। तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। इस प्रकरण में चालान पेश हो चुका है, लेकिन आगे की सुनवाई कानूनी अड़चनों के कारण नहीं हो पा रही है।

इस मामले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता विनोद वर्मा को गिरफ्तार भी किया था। मामले में विनोद वर्मा के नोएडा स्थित निवास पर भी छापेमारी की थी। यही नहीं वो करीब तीन महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटे थे। इस मामले में सीबीआई ने करीब 2 सौ लोगों को गवाह बनाया है।

कार्यालय मुख्य अभियंता,
लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 18.11.2024

सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र.	नि.आ.सू.क्र. दिनांक	सिस्टम आईडी क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत
1.	105/CE/NH/TC/44-40/2024 (1st Call)	2024_MoRTH_834426_1	Balance Periodic Renewal Work in km. 14.200 to 25.530 and 31.540 to 55,700 =35.480 km. on N.H. 30 (Old N.H. 221) Jagdalpur-Sukma Road on EPC mode in the state of Chhattisgarh on EPC Mode ("EPC") basis.	14.695 Cr. (i/c GST)

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 02.01.2025 सुबह 11.00 बजे तक है।

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORT&H's) के ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app से डाऊनलोड की जा सकती है।

जी-242503877/10

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र,
रायपुर (छ.ग.)

रंजिश भरी सियासत से अमेरिका मुश्किल में

राजेश बादल

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने बचे-खुचे कार्यकाल में अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। जाते-जाते वे डोनाल्ड ट्रम्प की अगली सरकार के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। वे जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं। प्रचार अभियान के दौरान और उससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प और जो बाइडेन के बीच सियासी प्रतिद्वंद्विता अब रंजिश में तब्दील हो गई है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम न केवल अमेरिका को, बल्कि उसके समूचे पिछलग्गू देशों तथा यूरोप के देशों को भुगतना पड़ेगा। नाटो देश परेशान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वे अपनी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन कैसे करें? बीते ढाई बरस से तो यह गोरे राष्ट्र यूक्रेन-रूस की जंग में अमेरिका का साथ देते आए हैं। वे अपने सैनिक संसाधनों और हथियारों से यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। खुलकर रूस के विरोध में हैं। अलबत्ता कुछ देश दबी जबान में रूस का समर्थन करते हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार निश्चित रूप से रूस के पक्ष में खुलकर आएगी तो यूरोप के देशों के सामने धर्मसंकट खड़ा होने वाला है। यक्ष प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में वे अपनी नीतियों को किस तरह रूस के पक्ष में मोड़ेंगे। ट्रम्प तो रूस को सहयोग देने का ऐलान कर ही चुके हैं। पर इतनी आसानी से क्या अन्य देश खुलकर यूक्रेन के विरोध में खड़े हो जाएंगे?उनके संसाधन और खजाने से पहले ही यूक्रेन के लिए इतना पैसा बहाया जा चुका है कि उसकी भरपाई आसान नहीं है। इस पृष्ठभूमि में जो बाइडेन की नई घोषणा उनके लिए आफत बन गई है। दरअसल जो बाइडेन ने अपनी विदाई की बेला में निर्णय लिया है कि अमेरिका पहली बार अब लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्मी टेक्टिकल तंत्र और उसकी मिसाइलों का उपयोग रूस के खिलाफ यूक्रेन को करने देगा। यह फैसला लेने से पहले उन्होंने अपने सहयोगियों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया। इससे अमेरिकी प्रशासन तनाव में है। पेंटागन भी आगाह कर चुका है कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें अमेरिका के पास कम हैं और उसकी अपनी रक्षा के लिए ही हैं। यदि वे यूक्रेन को दे दी गईं तो ठीक नहीं होगा। शायद इसी वजह से अमेरिका अभी तक इस तंत्र के जरिये रूसी सीमा के अंदर मिसाइलों का इस्तेमाल करने के विरोध में रहा है। उसे आशंका थी कि इससे रूस और यूक्रेन की जंग विकराल आकार ले सकती है। कई यूरोपीय देश भी इसमें कूद पड़ेंगे। वैसे यूक्रेन एक साल से इन मिसाइलों का उपयोग अपने देश के अंदर घुस आई रूसी सेना के खिलाफ कर रहा है। इसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया था। रूस के भीतर इन मिसाइलों से हमले करने की अनुमति नहीं देने के कारण यूक्रेन खुश नहीं था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि रूस के अंदर यदि इन मिसाइलों से आक्रमण करने की उसे अनुमति नहीं मिलती तो यह एक हाथ पीछे बांधकर हमला करने का आदेश देने जैसा है। जो बाइडेन के इस फरमान के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का एक वर्ग कयास लगा रहा है कि बाइडेन का यह निर्णय रूस और यूक्रेन के बीच जंग को दो महीने में समाप्त करा सकता है। इसका मतलब यह भी है कि रूस की पराजय हो सकती है। यानी जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को यह श्रेय नहीं लेने देना चाहेंगे कि वे इस जंग को समाप्त कराएं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने प्रचार अभियान में कह चुके हैं कि वे एक दिन में यह जंग खत्म करा देंगे। ट्रम्प का आशय यह भी था कि वे यूक्रेन के नीचे से जाजम खींच लेंगे और मजबूर होकर यूक्रेन को रूस के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन के लिए अपना धन क्योंकर खर्च करे? इसीलिए ट्रम्प के एक प्रवक्ता ने बीते दिनों यह कहा था कि यूक्रेन को यह भूल जाना चाहिए कि वह रूस से अपने हारे हुए इलाके वापस ले सकता है। इनमें क्रीमिया भी शामिल है। उधर, बाइडेन के निर्णय ने यकीनन डोनाल्ड ट्रम्प की मुश्किल बढ़ाने का काम किया है। ऐसे निर्णय व्यक्ति के नहीं, बल्कि देश के होते हैं। दो महीने बाद वे सिंहासन संभालेंगे तो अमेरिका की बाइडेन सरकार के फैसलों को पलटना उनके लिए अत्यंत जटिल होगा। बोलचाल की भाषा में कहें तो जो बाइडेन ट्रम्प के लिए रायता फैला कर जा रहे हैं।

कैलाश का इस्तीफा, बड़े संकट का संकेत

ललित गर्ग

दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। दिल्ली सरकार के प्रमुख मंत्री कैलाश गहलोत ने जिस तरह से चुनावी वादों को पूरा न करने जैसे ऐसे अनेक मुद्दों का जिक्र करते हुए अपने पद एवं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है जो अरविंद केजरीवाल की छवि पर सीधी चोट करने वाले हैं। दिल्ली के विकास की बजाय 'आप' सरकार का सारा समय केंद्र सरकार से झगड़ा करने में बीतने की बात कहकर गहलोत ने आम आदमी पार्टी की एक बड़ी कमजोरी को उजागर किया है, जो 'आप' के लिये एक बड़ा राजनीतिक संकट का संकेत है। अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करके इस पार्टी का गठन किया, लेकिन खुद एवं उसके अन्य बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की यात्रा कर आये, अनेक मतभेदों, विवादों एवं केजरीवाल के अहंकार, गलत नीतियों के चलते पार्टी के कई दिग्गज नेता पार्टी से दूर होते चले गए, जिनमें किरण बेदी, कवि कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी और कपिल मिश्रा और अब कैलाश गहलोत जैसे नाम शामिल हैं। लगता है अब आम की झाड़ू ही नहीं, बल्कि आप के राजनीतिक मूल्य भी तार-तार हो गये हैं। आम आदमी पार्टी के बढ़ते संकट एवं गिरते राजनीतिक मूल्यों के कारण उसकी चुनौतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है।

कैलाश गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी को इस्तीफा भेजा है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। गहलोत ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए एक लम्बा पत्र केजरीवाल को भेजा है। उन्होंने इस्तीफे में यमुना की सफाई और शीशमहल निर्माण का मुद्दा उठाया है। गहलोत ने पत्र में आरोप लगाते हुए लिखा है कि जिस ईमानदार राजनीति के चलते वह आम आदमी पार्टी में आए थे, वैसा अब नहीं हो रहा है। उन्होंने पार्टी के संयोजक व पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीशमहल करार देते हुए कई आरोप भी लगाए हैं। ऐतिहासिक

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी इस पार्टी का यह हश्र एवं दूरगति राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है। आम आदमी पार्टी खुद को ईमानदारी के उच्चतम मानकों पर रखने का दावा भले ही करती रही हो, लेकिन उसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों को ध्वस्त ही किया है। आप का उदय एक ताज़ी हवा का झोंका था लेकिन आज वह दूषित राजनीति का पर्याय बन गया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैलाश गहलोत का इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिये उल्टी गिनती का द्योतक है, यह राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि गहलोत ने एक तो यह कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना को साफ नहीं कर सकी और स्थिति यह है कि वह पहले से अधिक गंदी हो गई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि 'आप' सरकार का सारा समय केंद्र सरकार से झगड़ा करने में बीतता है। भले ही 'आप' कैलाश गहलोत की इन बातों को यह कहकर खारिज कर सकती है कि वह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं और यह भी कहा जा सकता है कि गहलोत पर ईडी-सीबीआइ आदि का दबाव था। निश्चित ही गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। कैलाश गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स की कई रेड भी हो चुकी थी। वह जांच का सामना कर रहे थे। आप के इन बयानों में कुछ सच्चाई भी हो सकती है कि उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन बड़ा तथ्य है कि 'आप' दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकी है, वह केंद्र सरकार से बात-बात में झगड़ा मोल लेने के लिए जानी जाती है। इससे इन्कार नहीं कि केंद्र सरकार भी आम आदमी पार्टी से उलझती हुई दिखती है, लेकिन दिल्ली सरकार की छवि ऐसी बन गई है कि वह केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने का मौका ढूंढ़ती रहती है। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच हर मुद्दे पर खींचतान जारी रहने से सबसे अधिक नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ है। दिल्ली की कई समस्याएं नहीं सुलझ पाने, दिल्ली का अपेक्षित विकास न हो पाने एवं अपने चुनावी वादों को पूरा न करने के कारणों के लिये 'आप' नेताओं ने हमेशा ही केन्द्र सरकार एवं भाजपा को दोषी ठहराया है। गहलोत ने कहा कि पार्टी से जुड़ी उनकी यात्रा का उद्देश्य दिल्ली के लोगों की सेवा करना था, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि पार्टी सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रही है, जिससे दिल्लीवासियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में उनके सामने पार्टी से अलग होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

'आप' टकराव की राजनीति में व्यस्त रही, अच्छे गवर्नेंस और बेहतर राजनीति का दामन उसके हाथ से लगातार छूटता रहा। दिल्ली में पार्टी ने असंख्य मुद्दे उठाये लेकिन वह इन सबको आखरी मंज़िल तक नहीं पहुंचा पायी। यह भविष्य ही बताएगा कि कैलाश गहलोत का त्यागपत्र आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से महंगा पड़ेगा या नहीं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने अपने इस्तीफे में जिस तरह 'आप' की गलत नीति एवं केजरीवाल की अति-महत्वाकांक्षाओं का जिक्र किया, वह अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ पूरी आम आदमी पार्टी की साख को करारा आघात देने वाला है। यह एक तथ्य है कि आम आदमी पार्टी आज तक इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते अपने सरकारी आवास की साज-सज्जा पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने की क्या जरूरत थी? कैलाश गहलोत ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि 'आप' अपनी रीति-नीति से भटक गई है। केजरीवाल और उनके सहयोगी इससे सहमत नहीं होने वाले, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 'आप' की भ्रष्टाचार विरोधी राजनीतिक दल की छवि का बहुत अधिक क्षरण हुआ है। 'आप' ने नई तरह की एवं मूल्यों की राजनीति करने के जो तमाम दावे किए थे, वे दावे यदि खोखले नजर आने लगे हैं तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी अन्य किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। एक बड़ा सवाल है कि 'आप' की इस दुर्दशा के चलते क्या वह दिल्ली पर अपनी मजबूत पकड़ को क्या कायम रख पायेगी? क्या दिल्ली में भाजपा या अन्य दलों के लिये अब सत्ता तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ गयी है?

आप एवं उसकी सरकार के लिये अभी भी देर नहीं हुई है, ज़रूरत है कि वह जन मुद्दों के बीच प्राथमिकता तय करे। अनावश्यक टकराव से बचते हुए अपने एजेंडे को अमलीजामा पहनाये। जहां सत्ता में है, वहां अच्छा शासन दें और जहां विपक्ष में है, वहां ज्यादा रचनाशील और प्रतिरोधात्मक ताक़त बने। एक बड़ा मुद्दा है कि वह नेतृत्व और सांगठनिक संरचना को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत बनाये। अभी तक पूरी पार्टी अरविन्द केजरीवाल-केंद्रित है, वह पार्टी भले बन गई हो पर उसकी सांगठनिक संरचना एक ऐसे एनजीओ जैसी है, जिसका एक सर्वशक्तिमान निदेशक है और पूरा संगठन उसके निर्देश और रहमोकरम पर चलता है। यही कारण है कि एक से बढ़कर एक कद्दावर के आप नेता पार्टी छोड़ते रहे हैं। अगर 'आप' को राजधानी दिल्ली के दायरे में या इस दायरे के बाहर अपनी सुसंगत राजनीति से लोगों को लंबे समय तक प्रभावित करना है तो कथनी और करनी में समानता दिखानी होगी। आप को अपना दोगलापन दूर करना होगा। 'आप' के जीवन में सत्य खोजने पर भी नहीं मिलता। दोहरे मापदण्ड अपनाने के कारण 'आप' की हर नीति, हर निर्णय एवं हर कथन समाधानों से ज्यादा समस्याएं पैदा करता रहा है। जिन्दा कौमें पांच वर्ष तक इन्तजार नहीं करती, दिल्ली की जनता ने कई गुणा इंतजार कर लिया है। यह विरोधाभास नहीं, दुर्भाग्य है या सहिष्णुता कहें? जिसकी भी एक सीमा होती है। जो पानी की तरह गर्म होती-होती 50 डिग्री सेल्सियस पर भाप की शक्ति बन हाती है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

सारे वेदान्त को पढ़ जाइये उसमें ब्रह्मप्रतिपादक तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म और नेह नानाऽस्ति किञ्चन आदि जितने भी प्रमाण दिये गये हैं, सब ब्राह्मणभागान्तर्गत उपनिषद् आदि ग्रन्थों के हैं और उन सबको श्रुति वेद के नाम से लिखा है। इससे स्पष्ट है कि व्यास जी ब्राह्मण ग्रन्थों के विशिष्ट भाग उपनिषदों को वेद स्वीकार करते थे।

(6) पातञ्जल महाभाष्य में पतञ्जलि जी लिखते हैं कि वेदेपि- य एवं विश्वसृज: सत्राण्यध्यास्त इति तेषा- मनुकुर्णस्तद्वत् सत्राण्यध्यासीत सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते। (महाभाष्य पृ0 20)

अर्थ- वेद में लिखा है कि जो इस प्रकार ब्रह्मा के यज्ञों का अनुष्ठान करता है, उसका अनुकरण करने वाला भी ऐहलौकिक सुखों को प्राप्त होता है। यहाँ - ध एवं विश्वसृज ग्रादि जो वाक्य वेद के नाम से उद्धृत किया है, वह ब्राह्मणभाग में ही उपलब्ध होता है, अत: निश्चित हुआ कि पतञ्जलि जी की सम्मति में भी ब्राह्मणभाग वेद है।

(7) आश्वलायन श्रौतसूत्र के भाष्यकार श्री नारायणस्वामी लिखते हैं कि- गाथाशब्देन ब्राह्मणगता ऋच उच्यन्ते। (आश्वलायन श्रौतसूत्र 5। 6) अर्थात् - ब्राह्मण भाग में आने वाली ऋचाओं को गाथा कहते है। इसी प्रकार आश्वलायन गृह्यसूत्र (313।1) की वृत्ति में लिखते हैं कि- गाथा नाम ऋग्विशेषा:।

अर्थात् गाथा नाम विशेष ऋचाओं का है, इन दोनों प्रमाणों में ब्राह्मणभागान्तर्गत आने वाली गाथाओं को ऋचा केके नाम से स्मरण किया है। और ऋचाएं केवल वेद में ही होती हैं अत: ब्राह्मणभाग वेद है। निरुक्त (4।6) में तो स्पष्टतया ही ब्रह्म गाथामिश्र भवति अर्थात् वेद में ही गाथा भाग होता है ऐसा लिख दिया है।

क्रमश: ...

विश्व टेलीविजन दिवस

शौर्य पुंज

हर साल 21 नवंबर को दुनियाभर में 'वर्ल्ड टेलीविजन डे' मनाया जाता है। टेलीविजन के अविष्कार ने दुनियाभर में क्रांति ला दी है, ये एक ऐसा शक्तिशाली जनसंचार का माध्यम है जिससे मनोरंजन, शिक्षा, दूर दराज की खबरें और राजनीति से जुड़ी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं हासिल होती है।

पहला विश्व टेलीविजन मंच 21 नवंबर 1996 में शुरू हुआ, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व टेलीविजन दिवस का नाम दिया। आज के दिन हर देश में अलग-अलग जगह टेलीविजन पर आने वाले शो और उनकी भूमिका के बारे में लोगों में बैठकें की जाती हैं।

अपने आविष्कार के बाद से टेलीविजन लोगों के मनोरंजन का एक

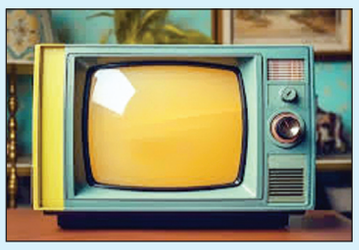

महत्वपूर्ण साधन रहा है। भारत में पहली बार 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन लॉन्च किया गया था। उस समय टेलीविजन ने देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौर में टेलीविजन पर 'हम लोग', 'बुनियाद', 'रामायण' और 'महाभारत' जैसे लोकप्रिय शो आते थे, जिन्हें देखने के लिए टीवी स्क्रीन के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी।

इसलिए, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से परे लोगों की राय को ढालने की शक्ति रखने वाले शिक्षा के स्रोत के रूप में टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व टेलीविजन दिवस की स्थापना की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 1996 में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। साल 1996 में आयोजित की गई पहली विश्व टेलीविजन फोरम की याद मे हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है।

बाद में संयुक्त राष्ट्र ने लोगों के निर्णय की क्षमता पर ऑडियो-विजुअल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और अन्य प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में इसकी संभावित भूमिका को पहचानने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।

इसलिए, टेलीविजन को सूचना, प्रणाली और जनमत को प्रभावित करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया। टेलीविजन वर्तमान में संचार और वैश्वीकरण का प्रतिनिधित्व भी करता है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि टेलीविजन समकालीन दुनिया में वैश्वीकरण और संचार के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है।

टेलीविजन ने लोगों का मनोरंजन करने के साथ-साथ परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलीविजन से परिवार के लोग एक दूसरे के करीब आ गए।

टेलीविजन सूचना और शिक्षा का प्रमुख स्रोत है, यह लोगों की निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। क्योंकि यह लोगों का ध्यान दुनिया में हो रहे संघर्षों की ओर खींचता है।

मोहम्मद यूनुस की हरकतें भारत की टेंशन बढ़ाने वाली

अभिनय आकाश

तारीख 25 अप्रैल 1971 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ी मीटिंग में देश के थल सेना अध्यक्ष से कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। 71 की वो जंग जब हिन्दुस्तान ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। जब हिन्दुस्तान ने 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। जब पाकिस्तान के 93 हजार सैनिक लाचार युद्ध बंदी बने। जब हिन्दुस्तान को बांटने का मंसूबा रखने वाला पाकिस्तान खुद टुकड़े-टुकड़े हो गया। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के युद्ध ने साबित कर दिया कि मुस्लिम एकता एक गलत धारणा थी, भारत का विभाजन एक गलत फैसला था और लोगों की भाषा और संस्कृति धर्म और जाति से ऊपर थी। 1971 की जंग में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए. बांग्लादेश नाम से जो नया मुल्क बना, उसने पाकिस्तान से दूरी ही बनाए रखी। बांग्लादेश में शेख़ हसीना के जाने के बाद से कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो भारत के लिहाज़ से ठीक नहीं माना जा रहा है। अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने में लगी है। पिछले सप्ताह, पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा। यह दोनों देशों के बीच पहला समुद्री संपर्क था। कराची से आए जहाज ने बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी तट पर माल उतारा. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा समुद्री संपर्क एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है।

जहाज एमवी युआन जियान फा झोंग बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंचा और पाकिस्तान से माल उतारने के तुरंत बाद रवाना हो गया। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार, 182 मीटर लंबा जहाज पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से सामान लेकर आया, जिसमें बांग्लादेश के प्रमुख परिधान उद्योग के लिए कच्चा माल और बुनियादी खाद्य

पदार्थ शामिल थे। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बड़ा शिपमेंट कपड़ा जैसे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले सोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश) का था, जिसे 115 कंटेनरों में लाया गया था। पहले, पाकिस्तान से कंटेनरों को बांग्लादेश पहुंचने से पहले किसी तीसरे देश से गुजरना पड़ता था। बाद में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ़ ने कहा कि सीधा शिपिंग मार्ग पूरे क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने कि दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल मौजूदा व्यापार प्रवाह में तेजी लाएगी और छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े निर्यातकों तक दोनों तरफ के व्यवसायों के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देगी। यह सीधी शिपमेंट ढाका में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा पाकिस्तानी सामानों पर आयात प्रतिबंधों में ढील देने के बाद आई है। पहले, ऐसे सामानों को आगमन पर अनिवार्य भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता होती थी जिसके परिणामस्वरूप लंबी देरी होती थी।

पाकिस्तान से बांग्लादेश में जहाज का डॉकिंग ढाका-इस्लामाबाद संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। दोनों देश 1971 में मुक्ति संघर्ष से पहले कभी एक राष्ट्र हुआ करते थे। 1971 के दौर की क्रूर युद्ध यादें, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, हाल तक बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानस में गहराई से अंकित रही। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूर रखना जारी रखा। दूसरी ओर, वह बांग्लादेश को भारत के करीब लाती रहीं। उदाहरण के लिए, अगस्त 2022 में, उनकी सरकार ने एक नए कमीशन किए गए चीनी निर्मित फ्रिगेट युद्धपोत पीएनएस तैमूर को चटगांव बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कंबोडियाई और मलेशियाई नौसेनाओं के साथ अभ्यास के बाद अपनी पहली यात्रा के बाद युद्धपोत अंतत: श्रीलंका के एक बंदरगाह पर पहुंचा। हालाँकि, हसीना के सत्ता बदर होने और भारत में पनाह लेने के बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को गहरा करते हुए एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया है। सीधे शिपिंग मार्ग के अलावा, दोनों देशों के एक-दूसरे के करीब आने के और भी संकेत मिल रहे हैं। 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्य तिथि ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में उर्दू शायरी के साथ मनाई गई। रिपोर्टों में कहा गया है कि कार्यक्रम में भाग लेने वालों ने जिन्ना की प्रशंसा की, यहां तक कि एक ने कहा कि जिन्ना हमारे राष्ट्र के पिता हैं और पाकिस्तान के बिना, बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं होता।

हसीना के निष्कासन के बाद से दोनों देशों के बीच वीजा प्रक्रिया भी सरल हो गई है। सितंबर में इस्लामाबाद ने घोषणा की कि बांग्लादेशी बिना वीज़ा शुल्क के देश की यात्रा कर सकते हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से तोपखाने गोला बारूद की ताजा आपूर्ति का भी आदेश दिया। ऑर्डर में 40,000 राउंड गोला-बारूद, विस्फोटकों के लिए मोम की स्थिरता में 40 टन आरडीएक्स और उच्च तीव्रता के प्रोजेक्टाइल, 2,900 की संख्या शामिल थी। हालाँकि यह इस तरह का पहला आदेश नहीं है, नई दिल्ली के अधिकारियों ने बताया है कि संख्याएँ सामान्य से कहीं अधिक थीं। 2023 में पिछला ऑर्डर 12,000 राउंड गोला-बारूद का था। ढाका विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर डॉ. शाहिदुज्जमां का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ सुरक्षा के तौर पर पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि की वकालत की थी।

ढाका और इस्लामाबाद के बीच गहराते रिश्ते पड़ोसी देश भारत के लिए चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश द्वारा अनिवार्य भौतिक निरीक्षण को ख़त्म करने से अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की आवाजाही को बढ़ावा मिल सकता है। विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने दिस वीक इन एशिया को बताया कि दोनों के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। उन्होंने 2004 की घटना का जिक्र किया जहां भारत में आतंकवादी संगठन उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम) के लिए हथियारों की एक खेप को बांग्लादेश के चटगांव में रोक दिया गया था। उस समय, भारत ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ने इस शिपमेंट को प्रायोजित किया था। कुगेलमैन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के खराब संबंधों को देखते हुए और बांग्लादेश में पाकिस्तान के किसी भी प्रकार के इरादे के बारे में दिल्ली के संदेह को देखते हुए, मुझे लगता है कि भारत के लिए इस विकास [पाकिस्तान जहाज की डॉकिंग] को काफी चिंता के साथ देखा जाएगा। आईएसआई इन नजदीकियों का फायदा उठाकर क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकती है। पहले भी बांग्लादेश के जरिए भारत में खलबली मचाने की कोशिशें होती रही हैं।

आज का इतिहास

1980 लास वेगास स्ट्रिप के एमजीएम ग्रांड होटल और कैसीनो में आग लगने से 85 लोग मारे गए।
1980 83 मिलियन से अधिक लोगों ने डलास के टीवी एपिसोड हू डन इट को हू आर जे।
1986 मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने संविधान अंगीकार किया।
1989 ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमंस में पहली बार कैमरे लगाए गए।
1996 लेबनान के राजनेता पियरे अमाइन गेमाएल , सीरिया की सैन्य उपस्थिति और लेबनान के राजनीतिक वर्चस्व की मुखर हत्या, जेडीह में हत्या कर दी गई थी।
1998 निन्दाडो ने द लीजेंड ऑफ ज़ेल्डा बुक रिलीज़ की: टाइम ऑफ़ ओरारिना
2002 बुल्गारिया,इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लेवानिया को नाटो ने संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण दिया।
2005 श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने पूर्व प्रधानमंत्री रत्नसिरी विक्रमनायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
2005 एरियल शेरोन, इजरायल के प्रधान मंत्री, लिकुड से इस्तीफा देने और एक नई पार्टी बनाने के अपने इरादे की घोषणा करते हैं, इजरायल के राष्ट्रपति को एक आम चुनाव बुलाने के लिए कहते हैं।
2006 एक यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी नीदरलैंड के अर्नहेम स्टेशन से टकरा गई, जिसमें 31 लोग घायल हो गए। पुलिस मालगाड़ी के चालक को गिरफ्तार करती है, जिसने स्पष्ट रूप से एक लाल सिग्नल की अनदेखी की थी।
2006 एनास्टासियस द्वितीय की मृत्यु के बाद, सिम्माचस और लॉरेंटियस दोनों पोप चुने गए, जिससे एक ऐसा विद्वान पैदा हुआ जो 506 तक चलेगा।
2007 स्थानीय चुनावों के दौरान संघर्षों में छह लोगों के मारे जाने के बाद नाइजीरियाई सेना का आयोजन कानो राज्य में किया गया है।
2008 ऑटोमोबाइल की बिक्री कम होने के कारण, टोयोटा अपने जापानी अस्थायी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत से 6,000 से 3,000 तक की कटौती करता है।
2009 एक शोध के अनुसार, होमो फ्लोरेसेंसिस, एक विशिष्ट प्रजाति है जिसे वर्ष 2003 में खोजा गया था।
2009 चीन के हेइलोंगजियांग में एक कोयला खदान में विस्फोट होने से 108 सैनिकों की मौत हो गई।

रियो डी जेनेरियो में विश्व नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का पूरा लेखा-जोखा

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन के इतर इटली, ब्रिटेन इंडोनेशिया, नॉर्वे और पुर्तगाल सहित कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और संबंधों को बेहतर एवं मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। हम आपको बता दें कि मोदी नाइजीरिया की दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद रविवार को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो पहुंचे हैं।

इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात- मोदी ने इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की और सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने 'एक्स' पर एक 'पोस्ट' में कहा, ''रियो डी जेनेरियो जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। हमारी बातचीत रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित रही। हमने संस्कृति, शिक्षा और इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी बात की। भारत-इटली की दोस्ती ग्रह को बेहतर बनाने में बहुत योगदान दे सकती है।'' विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी बैठक के बारे में 'एक्स' पर पोस्ट किया। मंत्रालय ने कहा, ''रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रियो में जी20 ब्राजील शिखर सम्मेलन के इतर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की।'' विदेश मंत्रालय ने कहा, ''दोनों नेताओं ने दीर्घकालिक भारत-इटली द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने तथा इसमें गति प्रदान करने के लिए भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 का स्वागत किया।''

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात- मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से भी मुलाकात की और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। मोदी ने 'एक्स' पर दोनों नेताओं की तस्वीरें साझा करते हुए एक 'पोस्ट' में कहा, ''ब्राजील में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिलकर प्रसन्नता हुई। यह वर्ष विशेष है क्योंकि हम भारत-इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारी बातचीत वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित रही।'' विदेश मंत्रालय ने कहा, ''गर्मजोशी से भरे और मैत्रीपूर्ण संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 ब्राजील शिखर सम्मेलन के इतर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की।'' मंत्रालय ने कहा, ''प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति प्रबोवो को भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को इसके मौजूदा क्षेत्रों में और मजबूत करने के साथ-साथ संबंधों को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की।''

पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात- पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मोदी की बैठक के दौरान बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर केंद्रित रही। मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत पुर्तगाल के साथ लंबे समय से जारी संबंधों को महत्व देता है। हमारी बातचीत दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने पर केंद्रित रही। नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र सहयोग के कई अवसर प्रदान करते हैं। हमने मजबूत रक्षा संबंधों, लोगों के आपसी संबंधों और ऐसे अन्य विषयों पर भी बात की।'' विदेश मंत्रालय ने 'एक्स' पर कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रियो में जी20 ब्राजील शिखर सम्मेलन के दौरान पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-पुर्तगाल द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।''

नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मुलाकात- मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से भी मुलाकात की। उन्होंने 'एक्स' पर कहा, ''प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। हमारी आर्कटिक नीति ने भारत-नॉर्वे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया है। हमने इस बारे में बात की कि दोनों देशों के बीच निवेश संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था में। नवाचार और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पर भी चर्चा हुई।'' विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ''भारत-नॉर्वे संबंधों को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए''। मंत्रालय ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 ब्राजील शिखर सम्मेलन के इतर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से मुलाकात की। चर्चा में भारत-नॉर्वे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बातचीत विशेष रूप से 'भारत - यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) - व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते' (टीईपीए) पर हस्ताक्षर के बाद व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर केंद्रित रही। नेताओं ने भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।''

आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक से मुलाकात- शिखर सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने भी मोदी से मुलाकात की। भारत में जन्मी अर्थशास्त्री ने 'एक्स' पर कहा, ''रियो में जी20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने भुखमरी और गरीबी कम करने में भारत की अनेक सफलताओं के बारे में बताया। दुनिया के लिए सीखने लायक अनेक रचनात्मक पहल कीं।'' मोदी ने इसके जवाब में 'एक्स' पर लिखा, ''भारत खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन क्षेत्रों में हम अपनी सफलताओं के क्रम को जारी रखेंगे और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने की खातिर अपनी सामूहिक शक्ति और संसाधनों का उपयोग करेंगे।''

अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात- इससे पहले दिन में मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात की और उनसे संक्षिप्त बातचीत की। इस बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। मोदी ने सोमवार को जी20 शिखर सम्मेलन के इतर ब्राजील, सिंगापुर और स्पेन सहित विश्व के कई अन्य नेताओं से भी बातचीत की।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात- इसके अलावा, मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के साथ भी बात की। स्टॉर्मर ने नए साल में भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ब्राजील में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर अपने भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद उन्होंने यह घोषणा की। स्टॉर्मर और मोदी की बैठक के बाद 'डाउनिंग स्ट्रीट' (ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक कार्यालय एवं आवास) ने कहा कि उनका देश भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की कोशिश करेगा, जिसमें व्यापार समझौते के साथ-साथ सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना शामिल होगा। स्टॉर्मर के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। '10 डाउनिंग स्ट्रीट' द्वारा जारी बयान में द्विपक्षीय बैठक के बाद स्टॉर्मर के हवाले से कहा गया, '' भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता ब्रिटेन में नौकरियों तथा समृद्धि को बढ़ावा देगा। यह हमारे देश में वृद्धि और अवसर प्रदान करने के हमारे अभियान को एक कदम और आगे बढ़ाएगा।'' मोदी ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत को '' अत्यंत सार्थक'' बताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, '' भारत के लिए ब्रिटेन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले वर्षों में हम प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार व प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।''

फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात- इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की और अंतरिक्ष, ऊर्जा तथा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के प्रारंभ में पेरिस में ओलंपिक खेलों और पैरालिंपिक खेलों की सफल मेजबानी के लिए भी फ्रांस के राष्ट्रपति को बधाई दी। मोदी ने सोमवार देर रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलना हमेशा ही अत्यंत खुशी की बात होती है।'' उन्होंने कहा, ''हमने इस बारे में चर्चा की कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और भविष्य के ऐसे अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। दोनों देश लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे।'' प्रधानमंत्री ने मैक्रों को बधाई देते हुए और उनके साथ हुई बैठक की तस्वीरें भी पोस्ट कीं। मैक्रों ने 'एक्स' पर लिखा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है, क्योंकि भारत के साथ हमारी साझेदारी समृद्ध और बहुआयामी है।'' उन्होंने पोस्ट में कहा, ''हमने पिछले जनवरी में मेरी राजकीय यात्रा के दौरान शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।'' उन्होंने एक छोटा वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें दोनों नेता गले मिलते और हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना यात्रा क्यों है खास?

विवेक शुक्ला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदा विदेश यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में लघु भारत कहे जाने वाले कैरेबियाई टापू देश गुयाना की यात्रा पर 19 से 21 नवंबर तक रहेंगे। वे जब गुयाना पहुंचेंगे तो वहां पर बसे हुए लाखों भारतवंशियों के लिए एक तरह से दूसरी दिवाली होगी। गुयाना में दिवाली उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है, जो 'छोटी दिवाली' से शुरू होकर 'बड़ी दिवाली' तक चलता है। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मारीशस, सूरीनाम, फीजी, गुयाना और त्रिनिदाद और टोबैगो को लघु भारत कहती थीं। ब्रिटिश सरकार गुयाना में भी भारतवंशियों को गिरमिटिया समझौता के तहत गन्ने के खेतों में काम करवाने के लिए लेकर आई थी। ब्रिटेन का उपनिवेश था गुयाना। ब्रिटिश गुयाना में काम करने के लिए अपने अफ्रीकी आदि देशों के अन्य उपनिवेशों से भी मजदूर लेकर आए थे। गुयाना की आबादी में भारतवंशी 50 फीसदी के आसपास हैं। अत: आज के गुयाना में ज्यादातर भारतीय और अफ्रीकी मूल के ही लोग हैं। भारतवंशियों में अधिकतर हिंदू हैं। गुयाना का इतिहास रहा है कि वहां भारतवंशी मुख्य रूप से पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी-सिविक (पीपीपीसी) को और अफ्रीकी-गुयाना मूल की जनता पीपल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) के हक में ही वोट देते हैं। वैसे पीएनसी में डोनाल्ड रामोतार जैसे भारतवंशी नेता भी हैं इसलिए यह कहना भी पूरी तरह से उचित नहीं होगा कि सारे भारतवंशी पीपीपीए के साथ ही रहते हैं। भारत के विपरीत गुयाना में मतदान अभी बैलेट पेपर से ही होता है। वहां पर अभी ईवीएम मशीनें नहीं आई हैं। पीपीपीसी की स्थापना गुयाना के पहले राष्ट्रपति छेदी जगन ने की थी। गुयाना में अब भारतवंशी राजनीतिक रूप से बिखर गए हैं। वे पहले एक दल विशेष के साथ ही खड़े होते थे। इसके चलते वहां पर भारतवंशी बेहतर स्थिति में थे। भारतवंशियों के संरक्षक के रूप में स्थापित हुए थे छेदी जगन। छेदी जगन के पिता जगन और मां जगाओनी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से गुयाना ले जाए गए थे। उनके पिता और मां के साथ उनकी दादी और चाचा भी गुयाना लाए गए थे। उनके पिता गन्ने के खेतों में मजदूरी करते और छेदी जगन 11 भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। उन्होंने गिरमिटिया का संघर्ष करीब से देखा था। वे 1961 में गुयाना के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। वे 1992-1997 में गुयाना के फिर राष्ट्रपति बने, पर उनकी मृत्यु के बाद भारतवंशी बिखरते गए। वर्तमान में पूरी दुनिया की गुयाना पर नजरें हैं, क्योंकि इधर कच्चे तेल के अकूत भंडार मिले हैं। इस कारण माना जा रहा है कि इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है। कहने वाले कहते हैं कि गुयाना निकट भविष्य में संसार के दस सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है गुयाना में आठ अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है। यह सच में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। गुयाना में तेल के भंडार एक्समोबाइल नाम की कंपनी ने खोजे हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव: कांग्रेस और आप के बीच आवागमन शुरू

अशोक गुप्त

दिल्ली विधानसभा के चुनाव पास आ रहे हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आवागमन शुरू हो गया है। कोई कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में जा रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जा रहा है। आज ही खबर आई है कि कांग्रेस नेता वीर सिंह धींगान ने कांग्रेस का हाथ झटक कर आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया। उसी के नीचे दूसरी खबर छपी थी कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी इशराक खान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वैसे कुछ दिनों से ऐसी खबरें बिला नागा रोज आ रही है, ऊपर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में जाने की खबर और नीचे आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जाने की खबर।

वैसे पिछले नगर निगम चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे क्षेत्र से कांग्रेस के पुराने चुनाव हारे विधायक सुभाष मल्होत्रा टिकट मिलने के आश्वासन पर आम आदमी पार्टी में आ गए तो आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष ने टिकट न मिलने की संभावना के कारण कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दोनों को टिकट मिल गए पर फायदा कुछ नहीं हुआ। चुनाव परिणाम आया तो

सीट बीजेपी जीत गई। वैसे इस आवागमन में कुछ अस्वाभाविक नहीं है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक जैसी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी बनी तो उसने कांग्रेस की जमीन हथियार कर ही अपना झोंपड़ा बनाया। यह बात और है कि उस झोंपड़ी को धीरे-धीरे शीश महल में बदल दिया। जो लोग परंपरा से कांग्रेस को वोट दिया करते थे, झुग्गी वाले, रिक्शा वाले, अवैध कॉलोनी वाले, पैसे लेकर वोट बेचने वाले, वे सब आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गए। इन वर्गों के वोट कांग्रेस से हटकर आम आदमी पार्टी में चले गए तो कांग्रेस का दीवाला निकल गया और आम आदमी पार्टी की दुकान चल गई। दुकान को और अच्छा चलने के लिए आम आदमी पार्टी ने इन तबके के लोगों को विशेष रूप से लुभाने के लिए बिजली और अपनी कुछ सीमा तक मुफ्त पानी देने का वादा कर दिया तो उनकी दुकान और अच्छे से चल गई। उधर महिला वोटरों को लुभाने के लिए बस यात्रा फ्री कर दी, फिर भले ही सरकार का दीवाना निकलता हो तो निकले। लीपा पोती करके गाड़ी भले ही खिंच रही हो पर दिल्ली वालों को ना तो नई सड़क मिल पाई, ना प्रदूषण काबू हुआ। पानी का तो हाल ही बेहाल है। कभी आया तो कभी नहीं आया, आया भी तो कभी-कभी गंदा भी आता रहा. अब जल बोर्ड का घाटा कौन भरेगा। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर हल्ला बोलकर आम आदमी पार्टी ने अपना नई दुल्हन का चिकना चुपड़ा चेहरा दिखाया और कांग्रेस के वोटरों को अपना दीवाना बना लिया। अब काठ की हांडी कितनी देर तक चढ़ती, भ्रष्टाचार का शोर मचाकर सत्ता में आए खुद भ्रष्टाचारी बन बैठे। कांग्रेस को तो फिर भी पुराना अनुभव था, इसलिए सब कुछ कर करके भी पकड़े नहीं जाते थे पर नए लोगों को इतना अनुभव नहीं था, इसलिए जल्दी ही पकड़ में आ गए। अब हालात यह है कि जनता की नजर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक जैसी पार्टियां हो चुकी हैं। जिसे कांग्रेस में टिकट मिलने की संभावना नजर नहीं आती, वह आम आदमी पार्टी में चला जाता है और जिसे आम आदमी पार्टी में टिकट मिलना मुश्किल लग रहा हो, वह कांग्रेस में आ जाता है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बढ़ता असंतुलन

के पी कृष्णन

भारतीय संविधान राज्य के काम को चार हिस्सों में विभाजित करता है- (क) केंद्रीय सूची, (ख) राज्य सूची, (ग) समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है और (घ) ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची जो ग्राम और शहर स्तर की सरकारों की भूमिका को परिभाषित करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि केंद्रीय सूची के मामले पूरी तरह केंद्र सरकार और लोक सभा की निगरानी में आते हैं।

एक पल के लिए सोचें तो पता चलेगा कि यह सही नहीं है। संविधान में द्विसदनीय विधायिका की कल्पना की गई है। लोक सभा के अलावा राज्य सभा भी है। राज्य सभा में 'राज्यों के प्रतिनिधि' होते हैं जिन्हें राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्य सभा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिये सभी राज्यों की विधान सभाओं के जरिये किया जाता है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों को दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए संसद की अनुमति जरूरी है। धन विधेयकों के अलावा सभी कानूनों को लोक सभा (जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी जाती है) और राज्य सभा (जो राज्यों के राजनीतिक दलों का नजरिया पेश करती है) की मंजूरी आवश्यक है। इस दृष्टि से देखें तो केंद्र राज्यों के कामकाज से अलग नहीं रह सकता। सभी राज्यों की विधानसभा का निर्वाचन ढांचा भी संसदीय कानूनों को आकार देने में मददगार साबित होता है।

संविधान सभा की बहसों में देश के संघवाद पर बहुत गहरी चर्चा की गई थी। यही वजह है कि इसमें तरह-तरह के संतुलन शामिल किए गए ताकि शक्ति के केंद्रीकरण से होने वाली ज्यादतियों से बचा जा सके।

केंद्र स्तरीय नियामकों ने इसे बदल दिया इस व्यवस्था में हमने सांविधिक नियामकीय प्राधिकारों (एसआरओ) का उभार देखा। आज, देश में केंद्रीय स्तर पर 20 से अधिक एसआरए हैं इनमें से प्रत्येक को कानून ने अपने क्षेत्र विशेष में कानून बनाने और उसका प्रवर्तन करने का अधिकार दिया है जिन्हें नियमन कहा जाता है।

उदाहरण के लिए देश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के 50 से अधिक परिचालन नियम हैं। वे कई अहम मुद्दों को कवर करते हैं। इसमें सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटीकरण की जरूरतें, पोर्टफोलियो प्रबंधकों का नियमन, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंज आदि सभी शामिल हैं। सेबी की अनुपस्थिति में ऐसे विषयों का संचालन एक समर्पित संसदीय कानून से होगा। इतना ही नहीं, इन नियमन में आए दिन संशोधन भी होता है।

उदाहरण के लिए अगर सेबी के पोर्टफोलियो प्रबंधकों

से जुड़े नियम को लें तो वे 2020 में जारी हुए थे और बीते तीन वर्षों में उनमें चार बार संशोधन किया गया है। बिना सेबी के ऐसे संशोधन करने के लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होती।

संसदीय विधान निर्माण एक श्रम साध्य काम है जिसके बारे में पूरी तरह अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। प्रतिभूति बाजार जैसे क्षेत्रों में बाजार के हालात के मुताबिक विशेषज्ञता और तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, ऐसे में संसद ने सेबी अधिनियम बनाया और इसने सेबी के अधिकारियों को यह शक्ति दी कि वे कानून बना सकें। अधिकांश अन्य एसआरए के लिए भी यही सच है।

नियामकीय कागजात में इस बात को चिह्नित किया जाता है कि एसआरए के डिजाइन में स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का अभाव नजर आता है। यह बात इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि एसआरए उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो अन्यथा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई विधायिका करती। विकसित देशों में ऐसे न्यायिक निर्णय गहन जांच के अधीन होते जा रहे हैं। अमेरिका के कुछ विनियमित क्षेत्रों की बात करें तो वहां इसके चलते एसआरए की नियामकीय शक्तियां वापस भी ली गई हैं।

भारत में भी नियामकों की कानून बनाने की बेलगाम शक्ति और इस दौरान लोकतांत्रिक वैधता की कमी पर अदालतों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बात जिस पर व्यापक तौर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है वह यह है कि केंद्र सरकार के नियामकों ने संघीय तोलमोल की क्षमता में संशोधन किया है जो भारतीय संविधान को आधार प्रदान करती रही है। इससे राज्यों की शक्ति में कमी आई है। जब केंद्र सरकार संसदीय कानूनों के माध्यम से काम करती है तब राज्यों के पास यह शक्ति रहती है कि वे अपनी बात कह सकें।

एसआरए द्वारा बनाए जाने वाले नियमन के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि नियमन को जारी करने के लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। एसआरए के विधायी ढांचे में संसद के दोनों सदनों के समक्ष विनियमन पेश करने तथा अधीनस्थ कानून पर संबंधित समितियों की जांच की व्यवस्था करके लोकतांत्रिक कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। संभावित रूप से यह संघवाद की कमी के उपचार के रूप में भी काम कर सकता है।

एक विश्लेषण दिखाता है कि सन 1999 से 2022 के बीच के 23 वर्षों में अधीनस्थ विधानों पर राज्य सभा की समिति ने एसआरए द्वारा बनाए गए चार कानूनों की समीक्षा की। संदर्भ के लिए प्रतिभूति नियामक ने 1992 में अस्तित्व में आने के बाद 661 नियमन जारी किए। दूसरे शब्दों में कहें तो संघीय घाटे की बात सही है।

यह किस तरह मायने रखता है, इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। शहरी स्थानीय निकायों को पैसे उधार लेने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। बॉन्ड बाजार के विकास के साथ ही बड़ी तादाद में म्युनिसिपल बॉन्ड संस्थागत उधारी की जगह ले रहे हैं।

म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर सेबी ने जो नियम बनाए हैं उनके मुताबिक राज्य सूची के एक विषय पर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की नियामकीय शाखा का नियंत्रण है। जाहिर है यह घाटा उन्हें प्रभावित कर रहा है।

इस आलेख को लिखने के पीछे मुख्य मुद्दा यही है कि देश में केंद्रीय नियामकों का जिस प्रकार उभार हुआ है वह संविधान सभा द्वारा परिकल्पित संघीय योजना के अनुरूप नहीं है। जांच और संतुलन की व्यवस्था से इस विचलन को ठीक उसी तरह से संबोधित करने तथा समझने की जरूरत है जैसे हम भारतीय राज्य के विकास के किसी अन्य पहलू को संबोधित करेंगे, जहां संवैधानिक जांच और संतुलन कमजोर हैं। सन 1809 में अमेरिकी विचारक थॉमस यू.पी. चार्लटन ने कहा था, 'शाश्वत सतर्कता ही आजादी की कीमत है।' हमारे देश के लिए भी यही सच है।

प्रश्न यह है कि क्या करने की आवश्यकता है? विचारकों को इस विषय पर बहस करने की आवश्यकता है कि कैसे विविध रास्तों का इस्तेमाल करके इस समस्या को बेहतर बनाया जा सकता है।

इसमें शामिल हैं- (क) राज्य प्रशासन द्वारा नियमन निर्माण के लिए अधिक विस्तारवादी शक्तियां देना, (ख) संसद की स्थायी समिति के काम में सुधार और राज्य सभा के अधीनस्थ विधानों पर निगरानी, (ग) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, उदाहरण के लिए अमेरिका की मौद्रिक नीति समिति के समकक्ष जिसमें क्षेत्रीय सदस्य होते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के अपने ज्ञान को मतदान में शामिल करते हैं।

इराक-ईरान युद्ध की कैसे हुई शुरुआत

मृत्युंजय कुमार राय

9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अल कायदा और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग के बाद दुनिया ने आईएसआईएस का उपद्रव देखा। इस्लामिक आतंकवाद के इस दौर से पहले श्रीलंका में लिट्टे ने कोहराम मचा रखा था और कम ही लोगों को याद होगा कि आत्मघाती हमले इसी संगठन की देन हैं। लेकिन आतंकवाद का साया दुनिया पर काफी पहले से रहा है, भले ही समय के साथ उसका चेहरा बदलता गया हो। बेन मैकिनटायर की किताब 'The Siege' में एक ऐसी घटना के बारे में लिखा गया है, जो अस्सी के दशक की शुरुआत की है। 1980 के अप्रैल में लंदन स्थित ईरान की एंबेसी में आतंकवादी घुसे और 26 लोगों को बंधक बना लिया। इससे एक साल पहले ही ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिससे वहां कट्टरपंथी सत्ता में आए और आज तक वहां गद्दीनशीन हैं। उससे इस हमले का नाता यह था कि एंबेसी में लोगों को बंधक बनाने वाले एक ऐसे उग्रवादी संगठन के सदस्य थे, जो ईरान में अरबों के लिए अलग देश चाहता था। यह घटनाक्रम कोई हफ्ते भर चला और यह एंबेसी में ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस (एसएएस) के घुसने के साथ खत्म हुआ।

एसएएस से आज विदेशी सिनेमा और सीरियल्स के जरिये दुनिया वाकिफ है, लेकिन ब्रिटेन के इस खास दस्ते के बारे में तब बहुत कम लोग जानते थे। एसएएस को दूसरे वर्ल्ड वॉर में नाजियों के हवाई जहाजों को गुपचुप तरीके से उनके इलाके में घुसकर तबाह करने के लिए बनाया गया था। खैर, बेन मैकिनटायर की किताब उस घटना के बहाने पश्चिम एशिया की राजनीति से भी रीडर्स को वाकिफ कराती है। वही पश्चिम एशिया जहां आज भी एक युद्ध चल रहा है।

यह किताब नॉन-फिक्शन है, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इसमें घटना के किरदार लाए गए हैं, उससे यह किसी रोमांचक फिक्शन से कम नहीं लगती। इसमें ट्रेवर लॉक नाम के एक पुलिस कॉन्स्टेबल का जिक्र है, जो एंबेसी की रक्षा में तैनात थे। वह ड्यूटी के दौरान जब चाय लेने गए,

तभी आतंकवादी एंबेसी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। आतंकियों ने ट्रेवर को भी बंधक बना लिया था। इस दौरान उन्हें हमेशा यह डर सताता रहा कि कहीं उनके पास जो हथियार है, वह आतंकवादियों की नजर में न आ जाए। बंधकों को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों से बातचीत की खातिर वहां भेजे गए फ्रेड लुफ एक और किरदार हैं। वह इस पूरे घटनाक्रम से इतने परेशान हो गए कि उन्हें वापस बुलाना पड़ा। बाद में वह अफ्रीका चले गए और ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। इन आतंकवादियों के बारे में दिलचस्प बात यह थी कि उन्हें ईरान के शाह से भी शिकायत थी, जिन्हें हटाकर कट्टरपंथी सत्ता में आए थे। वहीं, वे कट्टरपंथी शासकों को भी नापसंद करते थे। मैकिनटायर बताते हैं कि उन्हें इराक के सद्दाम हुसैन की शह मिली हुई थी। ईरान-इराक युद्ध की शुरुआत इस घटना से मानी जा सकती है। युद्ध इसके कुछ ही महीने बाद शुरू हुआ था। किताब में लिखा है कि पश्चिम एशिया में जियो-पॉलिटिक्स और आतंकवाद का तब जितना गहरा नाता था, आज भी उतना ही है।

ब्रिटेन में 1953 में महारानी की ताजपोशी के बाद एंबेसी की इस घटना ने मीडिया का सबसे बड़ा जमावड़ा देखा। उनके पास बेहद महंगे पोर्टेबल फोन और सैटेलाइट फोन थे। एक और बात के लिए इस घटना को याद किया जाता है। दरअसल, एसएएस की तब अखबारों और दूसरे मीडिया माध्यमों में खूब चर्चा हुई। ब्रिटिश एजेंसी के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं थी क्योंकि वह खुफिया तरीके से काम करने के लिए बनाई गई थी और इस घटना के बाद यह मुमकिन नहीं रहा।

बूम पर है वकालत का प्रोफेशन

सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा सिर्फ गिने-चुने प्रोफेशन में ही है। इन्हीं में से एक 'लॉ' भी है। लॉ का महत्त्व वैसे तो हमेशा से ही रहा है, परन्तु जिस हिसाब से लोगों में अपने अधिकारों एवं कानून को लेकर जागरूकता बढ़ी है, वकालत के पेशे ने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। भारत में सस्ती लॉ सुविधाओं के चलते विदेशी संस्थाएं भी भारतीय वकीलों की ओर देख रही हैं। यही वजह है कि आज वकालत का प्रोफेशन अपने बूम पर है।

भारत की लीगल एजुकेशन में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। कई यूनिवर्सिटीज एवं नेशनल लॉ स्कूल मिल कर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं यूजीसी की सहायता से इसकी गुणवत्ता को निखारा जा रहा है। यही कारण है कि देश में लीगल एजुकेशन में हालिया कुछ वर्षों में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। हालांकि किसी भी संस्थान का पाठ्यक्रम या विषय अन्य लॉ स्कूलों से अलग नहीं होते, परंतु संस्थान विशेष में पढ़ाई का तरीका उसे अपने आप में अनोखा बनाता है।

लॉ में हैं अनेक शाखाएं

लॉ के अंतर्गत आने वाले कोर्स का स्ट्रक्चर काफी फैला हुआ है। इसमें कई विषयों को शामिल किया जाता है। एक वकील अथवा जज को कई विषयों का ज्ञान रखना पड़ता है। अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से वे अपनी फील्ड भी चुनते हैं। इसके सब्जेक्ट को लेकर रोचकता इसीलिए बनी रहती है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स तथा एनवायरमेंट जैसे विषयों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। कुछ शाखाएं इस प्रकार हैं-

कॉरपोरेट लॉ- वर्तमान समय में वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कॉरपोरेट लॉ की उपयोगिता बढ़ गई है। इसके तहत कॉरपोरेट जगत में होने वाले अपराधों के लिए उपाय या कानून बताए गए हैं। कॉरपोरेट कानूनों के बन जाने से कॉरपोरेट जगत में होने वाले अपराधों को रोकने तथा कॉन्ट्रेक्ट नेगोसिएशन, फाइनेंस प्रोजेक्ट, टैक्स लाइसेंस और ज्वॉइंट स्टॉक से संबंधित काम किए जाते हैं। इसमें वकील किसी फर्म से जुड़ कर उसे कॉरपोरेट विधि के बारे में सलाह देते हैं।

पेटेंट अटॉर्नी- पेटेंट अटॉर्नी, पेटेंट लॉ का काफी प्रचलित शब्द है। इसका मतलब है कि एक ऐसा अधिकार, जिसके तहत कोई व्यक्ति अपना पूर्ण स्वामित्व रखता है। बिना उसकी मर्जी या सहमति के कोई अन्य व्यक्ति उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वह अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित (आंशिक या पूर्ण रूप से) करता है तो इसके बदले उस फर्म या व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करता है।

साइबर लॉ- हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग से साइबर क्राइम का भी ग्राफ बढ़ा है। आज इस कानून का विस्तार आम आदमी के साथ-साथ लॉ फर्म, बैंकिंग, रक्षा आदि कई क्षेत्रों में हो रहा है। इस कानून के तहत साइबर क्राइम के मुद्दों और उस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, इसकी जानकारी दी जाती है।

क्रिमिनल लॉ- इसे लॉ की दुनिया का सबसे प्रचलित कानून माना जाता है। इस कानून से हर छात्र का सामना पड़ता है। हालांकि इसमें भी शुरुआती चरण में कई तरह की दिक्कतों से दो-चार होना पड़ता है, परन्तु एक बार नाम हो जाने पर फिर सरपट दौड़ शुरू हो जाती है।

फैमिली लॉ- यह क्षेत्र महिलाओं का पसंदीदा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पर्सनल लॉ, शादी, तलाक, गोद लेने, गार्जियनशिप एवं अन्य सभी पारिवारिक मामलों को शामिल किया जा सकता है। लगभग सभी जिलों में फैमिली कोर्ट की स्थापना की जाती है, ताकि पारिवारिक मामलों को उसी स्तर तक सुलझाया जा सके।

बैंकिंग लॉ- जिस तरह से देश की विकास दर में वृद्धि हो रही है, ठीक वैसे ही बैंकिंग क्षेत्र का दायरा भी बढ़ रहा है। इसमें खासतौर पर लोन, लोन रिकवरी, बैंकिंग एक्सपर्ट आदि से संबंधित कार्यों का निपटारा होता है।

टैक्स लॉ- इस शाखा के अंतर्गत सभी प्रकार के टैक्स जैसे इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स से जुड़े मामलों को वकीलों की सहायता से निपटाया जाता है।

कब कर सकते हैं कोर्स

इसमें प्रवेश की पहली सीढ़ी 10+2 के बाद ही मिल जाती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा प्रायोजित पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में छात्रों को बुनियादी चीजों को लेकर स्पेशलाइजेशन तक की जानकारी दी जाती है, जबकि ग्रेजुएशन के पश्चात एलएलबी (तीन वर्षीय, पार्टटाइम/फुलटाइम) तथा उसके बाद एलएलएम (2 वर्षीय) में दाखिला आसान हो जाता है। बीए एलएलबी में छात्र को किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड जैसे कॉरपोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, बैंकिंग लॉ, टैक्स लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, रीयल एस्टेट लॉ आदि में विशेषता हासिल करनी होती है। कोर्स के प्रश्चात छात्र को एक से दो वर्ष तक इंटर्नशिप या किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के सहायक के रूप में काम करना पड़ता है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया या अन्य किसी संस्था में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है।

आवश्यक स्किल्स

इस प्रोफेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें छात्र जीवन से ही जुझारू प्रवृत्ति अपनानी पड़ती है। किताबों एवं घटनाओं से निरंतर जुड़े रहना किसी भी प्रोफेशनल को आगे ले जाता है। रिसर्च एवं एनालिसिस के आधार पर ही किसी विषय पर कमांड हासिल हो सकती है, इसलिए मेहनत करने से भागे नहीं। एक एडवोकेट के रूप में आपको मृदुभाषी, वाकपटु, मेहनती तथा लीडर जैसे गुण भी अपनाने पड़ते हैं। महज परीक्षा पास करने से ही एक अच्छा वकील नहीं बना जा सकता, बल्कि तार्किक, धैर्यवान, एकाग्रता, बहस करने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा पिछले केसों के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाला भी होना चाहिए। आपके पास एक अच्छी लाइब्रेरी तथा किताबों का संग्रह भी आवश्यक है।

कैसे लें लॉ कॉलेज की जानकारी

जहां एक ओर नामी लॉ कॉलेजों की भरमार है, वहीं फर्जी संस्थानों की भी कमी नहीं है। ऐसे फर्जी संस्थान विज्ञापन के माध्यम से अपने संस्थान का 100 प्रतिशत प्लेसमेंट दर्शाते हैं, इसलिए एडमिशन से पूर्व उस संस्थान की सत्यता की जांच-परख अवश्य कर लें। कोई भी इच्छुक छात्र, जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहता है या वह संस्थान के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है तो 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' उसकी मददगार साबित हो सकती है। यह संस्थान कानूनी शिक्षा एवं व्यवसाय के साथ-साथ कानूनों में सुधार लाने के लिए अपने परामर्श भी देता है।

चुनौतीपूर्ण करियर विकल्प मेडिकल

डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन इससे पवित्र कोई दूसरा पेशा भी नहीं है। बीमारों को नया जीवन देना इनका धर्म है। कहा तो यहां तक जाता है कि डॉक्टर भगवान का ही दूसरा नाम है। यकीनन किसी अन्य पेशे को ऐसा दर्जा मिलना कठिन है, क्योंकि यह जीवन से जुड़ा है और जीवन से महत्त्वपूर्ण और क्या हो सकता है। इसलिए जो कोई डॉक्टर बनने का निर्णय लेता है, वह एक कठिन निर्णय लेता है। यही वजह है कि करियर के परंपरागत विकल्पों में सबसे चुनौतीपूर्ण विकल्प मेडिकल को माना जाता है।

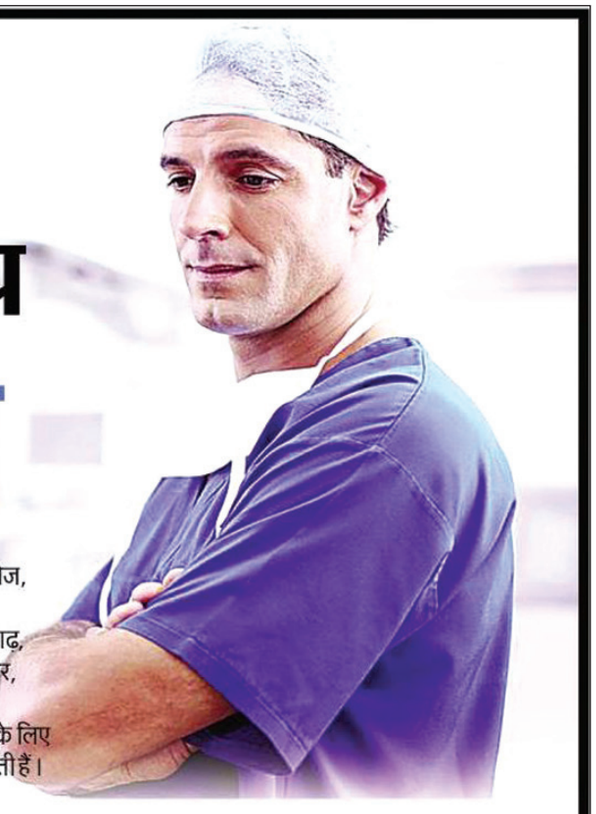

ऊपरी तौर पर लोग देखते हैं कि एक डॉक्टर खूब पैसे कमा रहा है और काफी व्यस्त रहता है। किन्तु इसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है, समर्पण कितना है, उदास क्षणों को झेलने का दम कितना है, मरीज की मौत पर विचलित न होने का विवेक कितना है, यह भी देखा व समझा जाना जरूरी है। यदि आप में ऐसा करने का दमखम है तो बेशक आप इस पेशे को अपना सकते हैं।

विशेषज्ञता

विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हर क्षेत्र में विशेषज्ञता पर जोर दिया जाने लगा है। जनरल फिजीशियन अब बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रारंभिक डिग्री लेने के बाद विशेषज्ञता की ओर बढ़ जाते हैं। इस पेशे में विशेषज्ञता के सहारे खुद को स्थापित करने की चुनौती हमेशा मौजूद है।

शाखाएं व डिग्री

मेडिसिन में कई शाखाएं हैं, जिनमें से आप अपनी रुचि व रुझान के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। आप एलोपैथी में जा सकते हैं, होम्योपैथी को अपना करियर बना सकते हैं या फिर आयुर्वेद को अपना सकते हैं। इनके अलावा, यूनानी मेडिसिन में भी आप पढ़ाई कर एक सफल चिकित्सक बन सकते हैं। इनमें से कुछ के पाठ्यक्रम साढ़े पांच साल के हैं तो कुछ चार साल के और कुछ तीन या साढ़े तीन साल के हैं। इनमें से किसी का चुनाव कर आप एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस, बीवीएससी/एएच इत्यादि की डिग्री ले सकते हैं।

प्रवेश परीक्षाएं

इन सभी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा ऑल इंडिया प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे, बीएचयू इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एएमयू, अलीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा इत्यादि के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

पात्रता

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
- अभ्यर्थी ने 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के साल विशेष के 31 दिसंबर या उससे पहले वह 17 साल पूरे कर ले।
- ऑल इंडिया प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इसमें पांच साल की छूट का प्रावधान है।
- ऑल इंडिया प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी को सिर्फ तीन अवसर ही मिलेंगे।
- अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा या समकक्ष 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उसने भौतिकी, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान व अंग्रेजी विषयों की पढ़ाई की हो और इन विषयों में उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 40 है।

फैशन इंडस्ट्री अपनी रचनात्मकता को आजमाएं

फैशन के क्षेत्र में अपना परचम लहराने के लिए प्रोफेशनल्स का कौशल, ज्ञान व प्रदर्शन ही उन्हें दूसरों से अलग करता है। सिर्फ चंद किताबें रट कर फैशन अथवा उसकी बिक्री करने की कला नहीं सीखी जा सकती। मौजूदा बाजार माहौल के कारण अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जरूरी हो गया है कि आप अपने कार्य कौशलों को बढ़ा कर फैशन इंडस्ट्री में अपनी रचनात्मकता को आजमाएं।

एक अध्ययन के मुताबिक भारत की फैशन इंडस्ट्री इस समय 200 करोड़ का आंकड़ा छू रही है तथा बड़े डिजाइनरों की सालाना बिक्री लगभग 25 करोड़ रुपए है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बाजार 35 बिलियन डॉलर के करीब है। यह इंडस्ट्री आने वाले सात वर्षों में भारतीय बाजार में ढाई हजार करोड़ तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना सकती है। फैशन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फैशन एंड डिजाइन प्रमोशन काउंसिल (एफडीपीसी) का गठन किया है। इस काउंसिल ने उभरते फैशन डिजाइनरों तथा स्कूल-कॉलेजों से पास हुए छात्रों के लिए 25 फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी किया है। भारत में फैशन उद्योग लगातार विकसित हो रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय फैशन के क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग बन चुका है। इंडिया फैशन वीक और भारत के प्रमुख शहरों में फैशन डिजाइनरों द्वारा वार्षिक शो जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से साफ हो गया है कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स व अन्य प्रतियोगिताओं में भारतीय सुंदरियां किसी से कम नहीं हैं।

कोर्स की रूपरेखा

महज बोर्ड पर किसी डिजाइन की स्केचिंग ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि छात्रों को इस इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विशेषज्ञता हासिल करनी होती है। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसके अंतर्गत गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल साइंस, अपैरल कंस्ट्रक्शन मेथड, फैब्रिक डाइंग एवं प्रिंटिंग, कलर मिक्सिंग एवं... ...कम्प्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) आदि क्षेत्रों में से किसी एक का चयन करना होता है। फैशन डिजाइनिंग में कई सारे कोर्स जैसे एक्सेसरीज एवं ज्वैलरी डिजाइनिंग, मॉडलिंग, गारमेंट डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग आदि को शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कोर्स इस इंडस्ट्री के लिए कारगर होते हैं, जैसे कि एमए, पीजी, बीए, अंडरग्रेजुएट डिप्लोमा, शॉर्ट टर्म लेवल आदि कोर्स।

फैशन जगत की शाखाएं

बात यदि फैशन इंडस्ट्री की शाखाओं की हो तो इसमें कई विकल्प निखर कर सामने आते हैं। छात्रों की अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्रों का चयन करना होता है। कुछ शाखाएं नीचे दी गई हैं-

फैशन कम्युनिकेशन

जब भारी संख्या में घरेलू और विदेशी ब्रांड, कंपनियां और डिजाइनर भारतीय बाजार पर धावा बोल रहे हों तो इन सबके लिए अपनी विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करना और बिक्री के लिए अधिकतम मात्र में उपलब्ध रहना अनिवार्य हो जाता है। यह बड़ा काम फैशन कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स आसान कर देते हैं।

फैशन स्टाइलिंग

भारत में फैशन स्टाइलिंग भले ही एक नया कॉन्सेप्ट हो, लेकिन यह तेजी से आकर्षक करियर में तब्दील हो रहा है। सफल स्टाइलिस्ट बनने के लिए फैशन के हर पहलुओं पर नजर, टीम में काम करने की क्षमता होनी जरूरी है। इसके कोर्स में मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, फोटोग्राफी, कम्प्यूटर एवं आईटी एप्लीकेशंस की जानकारी विकसित करने के लिए टूल्स, टेक्नीक्स और स्किल्स सिखाये जाते हैं।

फैशन जर्नलिज्म

योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए फैशन जर्नलिज्म में रोजगार के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में एक्सक्लूसिव राइटिंग और टीवी प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत अवसर हैं। फैशन जर्नलिस्ट फुलटाइम या फीलांस के रूप में काम करते हैं।

फैशन फोटोग्राफी

फैशन जर्नलिस्ट का दूसरा काम फोटोग्राफी से संबंधित होता है। अभिलाषा और कल्पना की उड़ान के धागों से बने कपड़ों की तस्वीरों को जर्नलिस्ट अपने पाठकों के लिए कुछ इस प्रकार से मढ़ता है कि पाठक उससे खुद को आसानी से जोड़ सकें।

डिजाइन डिपार्टमेंट

आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का काम बड़े स्तर पर होता है। इस यूनिट में डिजाइनर, कटिंग असिस्टेंट, स्केचिंग असिस्टेंट, जूनियर डिजाइनर आदि काम करते हैं। स्केचिंग असिस्टेंट जहां गारमेंट का टेक्निकल स्केच तैयार करता है, वहीं जूनियर डिजाइनर कटिंग का प्रारम्भिक कार्य तथा पहला सैंपल तैयार करता है।

मार्केटिंग एवं मर्केन्डाइजिंग

फैशन का ट्रैंड नित्य बदल रहा है। इस लिहाज से जिस व्यक्ति के पास मार्केटिंग एवं मर्केन्डाइजिंग की अच्छी समझ होगी, वह इस डिपार्टमेंट के योग्य हो सकता है। यह काम मुख्यत: मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लान पर आधारित सूचनाओं एवं कंपनी के पूरे दिशा-निर्देश पर आधारित होता है।

मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट

मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का हेड प्रोडक्शन मैनेजर होता है। वह कार्य की समय-सारिणी, लक्ष्यों, वर्कर्रों की ट्रेनिंग के अलावा प्रोडक्शन की क्वालिटी बनाये रखने संबंधी सभी गतिविधियों के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रोडक्शन मैनेजर हर चरण के कार्यों की निगरानी प्रोडक्शन असिस्टेंट की मार्फत कर सकता है।

फैशन को-ऑर्डिनेटर

इनका कार्य ग्राहक और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच तालमेल बिठाना होता है। इनका प्रमुख कार्य फैब्रिक का सही शेड, क्वालिटी, डिजाइन संबंधी परख, फैशन ट्रैन्ड के बारे में एडवांस जानकारी, खरीदारों के साथ मीटिंग व कपड़ों के डिजाइन व कलर तय करना आदि होता है।

मार्केट रिसर्च

ग्लोबल मार्केट समय के साथ बदलता रहता है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि बाजार की नजर क्या है तथा किस ट्रैंड को पसंद किया जा रहा है। प्रोडक्शन की प्रक्रिया डिजाइनरों द्वारा मार्केट रिसर्च के बाद ही शुरू की जाती है।

क्रिएटिविटी

ऊंची डिग्री न हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस क्षेत्र में जो चीज सबसे जरूरी होती है, वह है क्रिएटिविटी, रंगों की पहचान, शेड्स एवं टेक्स्चर आदि। सामान्यत: 10+2 (किसी भी स्ट्रीम में) उत्तीर्ण छात्र इससे संबंधित पाठ्यक्रमों में दाखिला पा सकते हैं। कुछ संस्थानों ने बारहवीं में 45 प्रतिशत का क्राइटेरिया तय कर रखा है तो कहीं-कहीं एंट्रेंस टैस्ट के आधार पर प्रवेश मिलता है। फैशन के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए फैशन की आधारभूत जानकारी, क्रिएटिविटी, क्लाइंट्स की जरूरतों, बाजार की मांग आदि की समझ आवश्यक है। ऐसे में एक फैशन डिजाइनर में अपने आइडिया को स्केच करने, टैक्सटाइल के प्रभावी उपयोग तथा विजुअलाइज संबंधी गुणों का होना जरूरी है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी 56 साल में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम

जॉर्जटाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को

गुयाना पहुंचे, जो 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दक्षिण अमेरिकी देश की पहली यात्रा है। जॉर्जटाउन हवाई अड्डे पर गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफ़ान अली और एक दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्रियों ने अभूतपूर्व गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनके आगमन पर दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक-दूसरे का अभिवादन किया। जॉर्जटाउन में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे। वे कैरेबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति इरफ़ान अली के निमंत्रण पर की गई यह यात्रा भारत और गुयाना के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाती है।

2029 चुनाव जीतने की तैयारी शुरू कर चुके हैं मोदी : चंद्रबाबू

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन

चंद्रबाबू नायडू लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे है। मोदी सरकार 3 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की अहम भूमिका है। 2024 के चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत नही मिल सकी। यही कारण है कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को टीडीपी और जदयू जैसे सहयोगियों की जरूरत है। हाल में ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2029 में होने वाले अगले आम चुनावों के लिए पहले से ही योजना बना ली है। 2024 एचटी लीडरशिप समिट में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह (मोदी) हमेशा अगले चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही इसकी योजना बना ली है और देश हित में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वह इसी तरह मिशन मोड में काम कर रहे हैं। नायडू ने कहा कि उनका दृष्टिकोण निर्णय लेने में केंद्र को प्रभावित करने का नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने का है।

झारखंड में 51 से अधिक सीटें हासिल करेगा एनडीए गठबंधन

रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे

चरण के लिए बुधवार को जारी मतदान के बीच झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा-एनडीए गठबंधन चुनाव में 51 से अधिक सीटें हासिल करेगा और सरकार बनाएगा क्योंकि लोग राज्य में सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार से असंतुष्ट हैं। झारखंड में लोगों का मूड हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार को बदलने का है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में उन्हें उनके शासन में नुकसान उठाना पड़ा है। लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने सीएम के पीए से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। काले धन के बिना यह संभव नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है तो उसके पास हमारे कुछ नेताओं पर आरोप लगाने के अलावा क्या विकल्प है। बीजेपी-एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं।

प्रशासन की मदद से वोट करने से रोकने की कोशिश : अखिलेश

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने

कहा कि भाजपा प्रशासन पर सपा समर्थकों को वोट देने से रोकने के लिए दबाव बना रही है। सपा समर्थकों को वोट करने से रोका जा रहा है। अधिकारी लोगों को वोट नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर एक बार पुलिस के लोग वोट करने से रोकते हैं तो दोबारा वोट करने के लिए जाएं। उन्होंने अधिकारियों का नाम लेते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। अखिलेश यादव मतदान के बीच लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा के लोग ऐसे अधिकारियों का वीडियो बनाएं और तस्वीरें लें जो कि उन्हें वोट नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के दोनों इंजन आमने-सामने आ गए हैं। इसलिए इन चुनाव में बेईमानी हो रही है। भाजपा बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली और दोनों डिप्टी सीएम इनके खिलाफ हैं।

केजरीवाल ने टिकट बंटवारे को लेकर रख दी शर्त

नईदिल्ली। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी

पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को उनके काम, जीत की संभावना और जनता की राय के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। उत्तर-पश्चिम और पश्चिम दिल्ली के आप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक में केजरीवाल ने विश्वास जताया कि पार्टी आगामी चुनाव जीतेगी क्योंकि वह सच्चाई के रास्ते पर चली है और उसे भगवान और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। केजरीवाल ने कहा कि मैं किसी भी रिश्तेदार, परिचित या दोस्त को टिकट नहीं दूंगा। कोई भाई-भतीजावाद नहीं होगा। मैं उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके काम, जीतने की संभावना और जनता की राय के आधार पर करूंगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि केजरीवाल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।

गुयाना में मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा

19 देश पीएम मोदी को दे चुके शीर्ष राष्ट्रीय सम्मान

जॉर्जटाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और बारबाडोस में सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले डोमिनिका ने हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया था। अब तक प्रधानमंत्री को दुनियाभर में 19 देशों की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। गुयाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान- द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा, वहीं बारबाडोस में पीएम मोदी को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान दिया जाएगा।

इससे पहले नाइजीरिया ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान %ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजर% से सम्मानित किया। इस सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दूसरी ऐसे विदेशी नेता बन गए हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है।पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, %नाइजीरिया के %ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर% पुरस्कार से सम्मानित होने पर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं और इसे भारत के लोगों को समर्पित करता हूं।% मोदी को दिया गया यह 17वां अतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सर्वाधिक है। एक सर्वे में उन्हें सबसे लोकप्रिय नेता करार दिया गया था। इतना ही नहीं कई देश भी उन्हें अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित कर चुके हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से अब तक 19 देशों के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों समेत संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

बता दें कि पीएम मोदी को साल 2016 में अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, फरवरी 2018 में फिलिस्तीन द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, अक्तूबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। वहीं, अप्रैल 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद और अप्रैल 2019 में ही रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा, पीएम मोदी को जून 2019 में मालदीव से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन, अगस्त 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, दिसंबर 2020 में अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, दिसंबर 2021 में भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग और इस साल मई में फिजी द्वारा ऑर्डर ऑफ फिजी और पापुआ न्यू गिनी द्वारा ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था।

वहीं, पिछले साल जून में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को %ऑर्डर ऑफ द नाइल% पुरस्कार से सम्मानित किया। यह मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। लीजन ऑफ ऑनर दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया गया है।

बिटकॉइन कांड पर महाराष्ट्र में सिसासत, भाजपा ने निशाने पर आए सुप्रिया सुले और नाना पटोले

नईदिल्ली। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े के खिलाफ धन वितरण के दावों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। इसके साथ ही बिटकॉइन मामले को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे आरोपों पर संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रिया सुले के ऐसे 4 ऑडियो हैं। आज सुप्रिया सुले कह रही हैं कि ये ड्ढ जनरेट किया गया है, ये मेरी आवाज नहीं है जबकि उनका अपना भाई कह रहा है कि ये उनकी आवाज है। तो साफ तौर पर हम सुन सकते हैं कि सुप्रिया सुले क्या निर्देश दे रही हैं और सिर्फ सुप्रिया सुले ही नहीं आप नाना पटोले को भी देख सकते हैं कि वो किस तरह अमिताभ गुप्ता जो कि कमिश्नर हैं उन्हें निर्देश दे रहे हैं।

संबित पात्रा ने कहा कि चैट बॉक्स में जो चैट हुई है उसमें सिग्नल ऐप में सुप्रिया सुले और नाना पटोले के अलावा कुछ और बड़े खिलाड़ी हैं। इस देश में लूट और भ्रष्टाचार के इस खेल में अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है तो वह सोनिया जी और राहुल जी हैं। और जिस तरह से कथित तौर पर ये चीजें हो रही हैं और इसमें करोड़ों रुपये शामिल हैं, 235 करोड़ रुपये जो हम सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल जी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भी दें कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। नाना पटोले को निर्देश दें? जिस तरह से सुप्रिया सुले हिदायत दे रही हैं कि मेरे साथ गेम मत खेलो, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है. और 235 करोड़ रुपये का ये लेनदेन दुबई से हो रहा है, इसके पीछे की हकीकत क्या है?

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा चोर है जो पकड़ा गया हो और कहे कि यह सच्चा आरोप है? जो पकड़ा जाता है वह कहता है कि यह झूठा आरोप है। तो स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी चोरी हुई है। बिटकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी कोई मजाक नहीं है, ये लेन-देन वाली चीजें हैं। वे अपने पदचिन्ह छोड़ते हैं। वहाँ एक पगडंडी है। ये बात जांच में साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोई तथ्य नहीं हैं और विनोद तावड़े जो हमारे महासचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से राहुल (गांधी) को चुनौती दी है कि वह आएं और सीसीटीवी देखें, खुद देखें और बताएं कि पैसा कहां है, कौन बांट रहा है। मैं सुप्रिया

सुले, राहुल (गांधी), नाना पटोले से कहता हूं कि उन्हें खुली चुनौती देनी चाहिए कि पूरी जांच होनी चाहिए।

बिटकॉइन विवाद में नाम आने पर भड़कीं सुप्रिया सुले

एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि वह क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी द्वारा उठाए गए पांच सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए, सुले ने कहा कि मैं उनके 5 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, जहां भी वह चाहें। समय उनकी पसंद का, जगह उनकी पसंद की और मंच उनकी पसंद का। मैं उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हूं क्योंकि सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

आरोप लगाने वाला जेल में, यह दिखाता है भाजपा कितनी गिर गई : शरद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चन्द्रं पवार) के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे। इसके अलावा उन्होंने नाना पटोले और सुप्रिया सुले के कथित वॉयस नोट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोपों के बाद पार्टी की ओर से मंगलवार को नाना पटोले और सुप्रिया सुले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। शरद पवार ने यह भी कहा कि उनकी बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले तथा कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले के खिलाफ भाजपा के आरोप ध्यान देने लायक नहीं हैं। आरोप लगाने वाला व्यक्ति जेल में है। यह दिखाता है कि भाजपा कितनी गिर गई है।

पुणे जिले के बारामती शहर में वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान शरद पवार ने कहा कि सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महाराष्ट्र का भविष्य तय करेगा। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। यह अच्छी बात नहीं है कि महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों से कम है। चुनाव परिणामों को लेकर अपने आकलन के बारे में पूछे गए सवाल पर शरद पवार ने कहा कि एमवीए को बहुमत मिलना चाहिए।

ऑडियो क्लिप में आवाज मेरी बहन की : अजित

महाराष्ट्र में मतदान के दिन एक बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रवींद्रनाथ पाटिल ने एनसीपी (सपा) नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले पर बड़ा आरोप लगा दिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रवींद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया है कि सुप्रिया सुले चुनावों के लिए धन जुटाने हेतु बिटकॉइन घोटाले की आय का उपयोग कर रही है। ये एक पूर्ण राजनीतिक लड़ाई में बदल चुका है। इन विवादों को और हवा देते हुए सुप्रिया सुले के चचेरे भाई और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दिन में दावा किया है कि उन्होंने रवींद्र पाटिल द्वारा सबूत के तौर पर पेश किए गए कथित ऑडियो क्लिप में सुले की आवाज पहचान ली है। उन्होंने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए अजित पवार ने बताया कि मैं आवाजों को पहचान सकता हूं। इस ऑडियो क्लिप की टोन से आवाज पता चलती है। उनमें से एक मेरी बहन की है और दूसरी वो है जिसके साथ मैं कापी काम कर चुका हूं। इस मामले की जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। सुप्रिया सुले ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि वो अजित पवार है और वो कुछ भी कर सकते है। राम कृष्ण हरि। इस बीच, सुले और उनके परिवार ने आरोपों के बीच आत्मविश्वास दिखाते हुए बारामती में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है।

खेल
प्रमुख समाचार

लियोनेल मेस्सी 14 साल बाद भारत में खेलने आएंगे

तिरुवनंतपुरम। भारतीय फुटबॉल फैंस के

लिए बेहद खुशखबरी है। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जल्द ही भारत लौटने की तैयारी में है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद किसी इवेंट के लिए नहीं बल्कि फुटबॉल मैच खेलने आ रहा है। इससे पहले अंतिम मैच लियोनेल मेस्सी ने वर्ष 2011 में कोलकाता में खेला था। ये मुकाबला साल्ट लेक में अर्जेंटीना और वेनेजुएला के बीच खेला गया था।

वहीं अब फुटबॉल के जादूगर पूरे 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद फिर से भारत लौटेंगे। ये भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बेहद खुशी का पल है। विश्व विजेता टीम अर्जेंटीना अगले साल भारत में अपना मैच खेलने वाली है। इसकी जानकारी केरल के खेल मंत्री अब्दुरहीमान ने दी है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राज्य सरकार की पूरी निगरानी में ये मैच आयोजित होगा। उन्होंने कहा, इस हाई-प्रोफाइल फुटबॉल इवेंट के आयोजन के लिए राज्य के व्यापारियों द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर की मेजबानी करने की केरल की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। लियोनेल मेस्सी ने आखिरी बार भारत में 2011 में खेला था, जब अर्जेंटीना ने वेनेजुएला के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लिया था। ये मैच गोल रहित ड्रॉ में समाप्त हुआ था। फुटबॉल आइकन के भारत में बहुत सारे प्रशंसक हैं। केरल में ऐसे फैंस की संख्या भी काफी अधिक है। हाल ही में मेजर लीग सॉकर की टीम इंटर मियामी में मेस्सी के शामिल होने से उत्तरी अमेरिका में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है, जिससे भारत में भी उनके प्रशंसक आकर्षित हुए हैं, जो अक्सर उनके मैच देखने के लिए देर रात तक जागते रहते हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कहां करें निवेश?

नईदिल्ली। वैश्विक समस्याओं जैसे युद्ध का खतरा, केंद्रीय बैंकों की कड़ी नीतियां और बाजार की ऊंची कीमतों ने शेयर बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया है। आने वाले समय में बाजार में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यह अस्थिरता केवल कुछ समय के लिए है। फर्म ने शेयर बाजार को लेकर लंबी अवधि में सकारात्मक रुख जताया है। फर्म का कहना है कि कंपनियां अपने कर्ज को घटा रही हैं और अगले दो साल में उनकी कमाई बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही, कई कंपनियां आर्थिक बदलावों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इक्विटी में निवेश जारी रखें, खासकर वो लोग जिन्होंने इसमें पहले से अच्छा पैसा लगाया है। जिन निवेशकों ने कम पैसा लगाया है, उन्हें धीरे-धीरे और प्लान के साथ इक्विटी में अपना निवेश बढ़ाने की सलाह दी गई है।

कोलकाता में गोदरेज बनाएगी शानदार रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट

नईदिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने एक परियोजना के निर्माण के लिए कोलकाता में 53 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है, जिसकी राजस्व क्षमता करीब 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भारत की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने कोलकाता के जोका में करीब 53 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने कहा, '' प्रस्तावित परियोजना में 13 लाख वर्ग फुट बिक्री योग्य क्षेत्र की विकास क्षमता होने का अनुमान है, जिसमें मुख्य रूप से आवासीय प्लॉट का विकास शामिल है। इसकी अनुमानित राजस्व क्षमता 500 करोड़ रुपये है।'' कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने कहा, '' यह भूमि अधिग्रहण भारत के प्रमुख शहरों में हमारी उपस्थिति को गहरा करने की हमारी रणनीति के अनुकूल है।

पोस्ट ऑफिस से हर महीने होगी 5550 रुपये की गारंटीड इनकम

नईदिल्ली। बाजार को जोखिम उठाए बिना अपने निवेश पर हर महीने गारंटडी इनकम चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (पीओएमआईएस) एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस सरकार समर्थित स्माल सेविंग्स स्कीम में आपका निवेश पूरी तर सुरक्षित रहता है। इस स्कीम में रू. 9 लाख (सिंगल अकाउंट) या रू. 15 लाख (जॉइंट अकाउंट) तक निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पीओएमआईएस में फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसका भुगतान हर महीने किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत सिंगल अकाउंट में न्यूनतम 1,000 रुपये निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम 9 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। वहीं, ज्वाइंट अकाउंट में निवेश की सीमा 15 लाख रुपये है। अधिकतम तीन लोग एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल है।

एसएमई आईपीओ के नियमों को सख्त करने की तैयारी

नईदिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज (एसएमई) के लिस्टिंग नियमों को सख्त बनाने की तैयारी में है। सेबी ने एसएमई लिस्टिंग के फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है. इसमें न्यूनतम आवेदन राशि दोगुना करने का प्रस्ताव भी शामिल है। साथ ही एसएमई आईपीओ के लिए कुछ नियमों को मेनबोर्ड इश्यू पर लागू नियमों के अनुरूप करने का प्रस्ताव रखा है। सेबी की ओर से एसएमई के लिए लिस्टिंग नियमों में सुधार का यह प्रस्ताव कुछ मार्केट प्रतिभागियों द्वारा एसएमई प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या के बीच आया है। सेबी के प्रस्तावों पर एक्सपर्ट का कहना है कि नियमों को सख्त बनाए जाने से चेक एंड बैलेंस बेहतर होगा। साथ ही कम्प्लायंस और बेहतर होगा।

एम.एस.एम.ई.ज को सहज व सस्ते ऋण के लिए 'स्पैशल बैंक' की जरूरत

डा. अमृत सागर मित्तल

सूक्ष्म, छोटे व मझोले उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को बैंकों से ऋण में आ रही मुश्किलों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आए दिन चिंता जताए जाने से बैंकों के काम-काज पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसलिए सरकार एम.एस.एम.ई.ज को सीधे ऋण की सहज उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्पैशल बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है।

स्माल इंडस्ट्रीज डिवैल्पमैंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) जैसा संस्थान कहने को एम.एस.एम.ई.ज के लिए समर्पित है, पर यह सीधे फंड देने की बजाय रीफाइनांस पर निर्भर है। कई राज्यों में इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कॉरपोरेशन व स्टेट फाइनांस कॉर्पोरेशन एम.एस.एम.ई.ज को सीधे ऋण दे रहे हैं, वहीं फंड की कमी से जूझ रहे पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन (पी.एस.आई.डी.सी.) व पंजाब फाइनांस कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी.) ने बीते कई साल से ऋण बंद कर दिए हैं। 4700 करोड़ रुपए की देनदारियों में घिरे पी.एस.आई.डी.सी. ने बीते 16 साल से कोई ऋण नहीं दिया।

अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट मुताबिक, 'भारत के केवल 14 प्रतिशत एम.एस.एम.ई.ज की सस्ते इंस्टीच्यूशनल ऋण तक पहुंच है, जबकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में अमरीका के 50 व चीन के 30 प्रतिशत एम.एस.एम.ई.ज सस्ते ऋण का लाभ ले रहे हैं। भारतीय एम.एस.एम.ई.ज को 25 लाख करोड़ रुपए की क्रैडिट कमी इस बात का संकेत है कि यदि उन्हें सीधे, सस्ते व सहज ऋण बढ़ाए जाएं तो देश में आर्थिक गतिविधियों व नौकरियों के नए अवसर और भी बढ़ाए जा सकते हैं। एम.एस.एम.ई.ज को समर्पित एक अलग बैंक की स्थापना से इन्हें

कारोबार विस्तार के लिए ऋण की कमी दूर हो सकेगी।

देश की जी.डी.पी. में 18 प्रतिशत योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र को नाबार्ड ने साल 2023-24 में 6.68 लाख करोड़ रुपए ऋण उपलब्ध कराए जबकि 27 प्रतिशत योगदान देने वाले एम.एस.एम.ई. सैक्टर को सिडबी ने केवल 84000 करोड़ रुपए के ऋण जारी कराए। कारोबार के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने को एम.एस.एम.ई.ज के लिए पूंजी जुटाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि आर.बी.आई. ने इन्हें प्राथमिकता वाले सैक्टरों को लक्षित 40 प्रतिशत ऋणों में शामिल किया है, पर ज्यादातर बैंकों के एम.एस.एम.ई.ज को निर्धारित लक्ष्य के 25 प्रतिशत ऋण भी जारी नहीं होते।

भारत के 6.40 करोड़ एम.एस.एम.ई.ज में भले ही 99 प्रतिशत बहुत ही छोटे कारोबारी हैं, पर इनके महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता। मैन्युफैक्चरिंग में 38.4 प्रतिशत व एक्सपोर्ट में 45 प्रतिशत योगदान के साथ देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद एम.एस.एम.ई.ज की सीमित क्रैडिट हिस्ट्री व अपर्याप्त कॉलेटरल गारंटी की वजह से कमर्शियल बैंकों तक पहुंच नहीं हो पाती, जिससे उनके लिए बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण पाना आसान नहीं होता।

हालांकि केंद्र सरकार ने एम.एस.एम.ई.ज के ऋण को बढ़ावा देने के लिए क्रैडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया जैसी कई पहल की हैं लेकिन इन्हें कारगर ढंग से लागू करना भी जरूरी है। एक अहम मुद्दा 10 से 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज की ऊंची उधारी लागत है, जो देश के कारोबारियों को चीन, अमरीका और यूरोपीय देशों के कारोबारियों के मुकाबले पिछाड़ती है। चीन में ब्याज दर 3.1, अमरीका में 4.37 और यूरोपीय देशों में एम.एस.एम.ईज को औसत 5.1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलते हैं।

अमरीका में एम.एस.एम.ईज केंद्रीय व राज्यों के कई कार्यक्रमों के जरिए आसानी से सस्ते ऋण हासिल करते हैं। 'स्माल बिजनैस एडमिनिस्ट्रेशन' लोन गारंटी के साथ बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों के ऋण के लिए प्रोत्साहित करता है। 'माइक्रोलोन प्रोग्राम' के तहत बिजनैस की कई जरूरतों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के अलावा वर्किंग कैपिटल, उपकरण व जमीन खरीदने के लिए भी ऋण दिया जाता है। इसके अलावा अमरीकी सरकार एम.एस.एम.ईज को लोकल बिजनैस के माहौल मुताबिक ऋण से मदद करती है।

सीजीपीएससी घोटाला

सीबीआई बढ़ाएगी जांच का दायरा, रसूखदारों के बीच खलबली

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पीएससी (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) भर्ती घोटाले में सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बजरंग इस्पात के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद रसूखदारों के बीच खलबली मच गई है। संकेत मिल रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़ने पर सीबीआई जल्द ही एक आईपीएस और एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को भी हिरासत में ले सकती है।

हाई कोर्ट की फटकार और गड़बड़ियों की पुष्टि- हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर याचिका में लगाए गए आरोप और प्रस्तुत सूची सही हैं, तो यह गंभीर मामला है। कोर्ट ने संकेत दिए थे कि अफसरों के बच्चों के चयन में गड़बड़ी हुई है।

पहली परीक्षा की जितनी चर्चा ,उससे भी इस मामले की हो रही- छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के गठन और उसके बाद अब तक जितनी भी परीक्षाएं सीजीपीएससी ने आयोजित की अमूमन सभी विवादों के घेरे में रहा है। सभी परीक्षाओं के बाद भर्ती का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। सबसे ज्यादा चर्चित वर्ष 2003 में आयोजित पहली परीक्षा रही। मौजूदा दौर में वर्ष 2021-22 में आयोजित परीक्षा में तो भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की सीमाएं ही लांघ दी है। छत्तीसगढ़ के युवाओं का भरोसा ही सीजीपीएससी के अफसरों ने तोड़ दिया है।

भ्रष्टाचार ने युवाओं का भरोसा तोड़ा-छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग पर पहले भी विवाद के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन 2021-22 की भर्ती में गड़बड़ियों ने सभी हदें पार कर दीं। परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की सूची में अफसरों और रसूखदारों के परिवार के सदस्यों के नाम ने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है।

छत्तीसगढ़ के युवाओं और जनता को अब सीबीआई की आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

सीबीआई जांच: भाजपा की जनहित याचिका से शुरू हुआ मामला

सीजीपीएससी 2021-22 भर्ती में गड़बड़ियों का मामला तब प्रकाश में आया, जब पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पीएससी और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ की युवाओं को न्याय दिलाने और घोटाले की सीबीआई जांच कराने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस वादे को पूरा करते हुए राज्य में प्रतिबंधित सीबीआई को इस घोटाले की जांच का जिम्मा सौंपा।

जांच के पहले चरण में दो गिरफ्तार, और नाम आने की संभावना

सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति बजरंग गोयल को गिरफ्तार किया है। अब चर्चा है कि जल्द ही एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पुलिस अफसर को भी गिरफ्त में लिया जा सकता है। सीबीआई की जांच की तेजी ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कुछ और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं।

ये है वो नाम, जिसे लेकर मचा है बवाल

● नितेश, डिप्टी कलेक्टर, पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी का पुत्र, सरनेम छिपाया गया ● साहिल, डीएसपी, पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बड़े भाई का पुत्र, सरनेम छिपाया गया ● निशा कोशले, डिप्टी कलेक्टर, पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह के पुत्र नितेश की पत्नी ● दीपा अजगले/आदिल जिला आबकारी अधिकारी, पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू ● सुनीता जोशी, लेबर आफिसर, पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी की बहन की पुत्री ● सुमित ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर, लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलखो का पुत्र ● नेहा खलखो, डिप्टी कलेक्टर, लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलखो की पुत्री ● निखिल खलखो, डिप्टी कलेक्टर, लोक सेवा आयोग के सचिव अमृत खलखो का पुत्र ● साक्षी ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर, बस्तर नक्सल आपरेशन के डीआइजी ध्रुव की पुत्री ● प्रज्ञा नायक, डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्री ● प्रखर नायक, डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार का पुत्र ● अन्यया अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता की पुत्री ● शशांक गोयल, डिप्टी कलेक्टर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद ● भूमिका कटियार, डिप्टी कलेक्टर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की पुत्री ● खुशबू बिजौरा, डिप्टी कलेक्टर, कांग्रेस नेता के ओएसडी के साढ़ू भाई की पुत्री ● स्वर्णिम शुक्ला,सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला का पुत्र ● राजेंद्र कुमार कौशिक, डिप्टी कलेक्टर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता का पुत्र ● मिनीक्षी गनवीर, डिप्टी कलेक्टर, गनवीर की पुत्री जो कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के साथ रहती हैं।

मार्च 2026 का यह दिन बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए आजादी का दिन होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के साथ एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे। उन्होंने बस्तर ओलंपिक खेलकूद के आयोजन में युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की। गृह मंत्री विजय शर्मा बीजापुर के मिनी स्टेडियम में चल रहे बस्तर ओलंपिक में पहुंचे।

इस दौरान वे बीजापुर की प्रसिद्ध मद्देड़ बाजा की धुन पर थिरकते हुए भी नजर आए। पुलिस विभाग की टीम की ओर से रस्सा कस्सी में भी हिस्सा लिया और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। वहीं उन्होंने जिले में संचालित स्पोर्ट्स अकादमी और खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि यही वह युवा हैं जो आने वाले समय में बीजापुर को देश दुनिया में नई पहचान दिलाएंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन के दौरान नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मार्च 2026 का दिन भले ही दूसरों के लिए आम दिन हो सकता है, लेकिन यह दिन बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए आजादी का दिन होगा क्योंकि इस दिन बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा।

इस दौरान उन्होंने तेलंगाना सरकार की मंत्री सीतक्का का उदाहरण देते हुए युवाओं से कहा कि सीतक्का भी पहले बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के साथ बंदूक लेकर घूमती थी। बाद में उन्हें समझ में आया कि यह सही रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बनी।

इस समय वे तेलंगाना सरकार में मंत्री हैं और लोगों के लिए विकास के काम ही नहीं बल्कि हर तरह के काम कर रही है। उन्होने कहा कि चीन की विचारधारा चीन में ही विफल हो गई है तो बस्तर में कैसे सफल हो पाएगा?

बस्तर में सड़कों का विरोध, पुल-पुलियों का विरोध, स्कूल भवनों का विरोध और स्कूल भवनों को बम में उड़ाना, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और बस्तर में शांति स्थापित होना चाहिए। इसीलिए आने वाला समय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मनसा अनुसार मार्च 2026 बस्तर की आजादी का दिन होगा।

भाजपा सरकार के राज में अपराधी बेलगाम, आम आदमी असुरक्षित

रायपुर। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में रोज हो रही हत्याओं पर कांग्रेस ने गहरी चिंता व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में अपराधी बेलगाम हो गये है। आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। रायपुर शहर में एक पखवाड़े में 17 हत्याएं हुई है। प्रदेश का हर नागरिक डरा हुआ है। महिलायें असुरक्षित है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ गयी है। एक ही दिन में राजधानी के विधानसभा के पास आमासिवनी में शराब दुकान के सामने दो-दो हत्याये हुई, पुरानी बस्ती थाने के चंद कदमों की दूरी पर पेट्रोल डालकर एक युवक को जिंदा जला दिया गया, तेलीबांधा में गवाह को धमकाने अपराधियों ने हमला कर दिया, दिनदहाड़े गोलियां चल रही है, गैंगवार हो रहे हैं।

भय के वातावरण में जीने को मजबूर है महिलाएं - वंदना राजपूत

रायपुर। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश में हर रोज लगभग 4 से 5 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आ रही है। 20 नवंबर को गुढ़ियारी में एक विवाहित महिला के साथ गैंगरेप की घटना घटती है। दिन पहले मुख्यमंत्री गृह ग्राम जशपुर जिले में 15 साल की एक नाबालिक बच्ची के साथ गैंगरेप घटना को अंजाम दिया जाता है वही बालोद में भी एक नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आता है । कोरबा में भी नाबालिक बच्ची से अनाचार के मामला सामने आता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा लगाने वाले की आंखों के सामने यह सारी घटनाएं घट रही है लेकिन अपनी सरकार के साख बचाने के लिए आंख बंद करके बैठे हैं और आंकड़े पर आंकड़े खेलते रहते हैं।

फार्मेसी काउंसिल के दागी, भ्रष्टाचारी अयोग्य रजिस्ट्रार को सरकार का संरक्षण,

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भाजपा सरकार पर वसूली गिरोह चलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सरकार का संरक्षण भ्रष्ट अधिकारियों को है, केवल कमीशनखोरी के लिए नियम कानूनों को दरकिनार कर अयोग्य कर्मचारियों को वसूली एजेंट के रूप में प्रमुख विभागों में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश के स्वस्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मेसी काउंसिल इसका बड़ा उदाहरण है जहां फर्जी डिग्री के आरोपी रहे, क्लास 3 के फार्मासिस्ट को रजिस्टर के पद पर बैठाया गया है। सरकार के संरक्षण में इस अयोग्य व्यक्ति के द्वारा एक निर्वाचित मेडिकल काउंसिल के सदस्य के खिलाफ दुर्भावना पूर्वक कार्रवाई की गई है जो न केवल अनुचित है बल्कि वैधानिक भी है।

हसदेव जंगल की अवैध कटाई के दौरान आदिवासी युवक सहित तीन मजदूरों की मौत के लिए साय सरकार जिम्मेदार

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने हरदेव अरण्य के जंगलों में अवैध कटाई के दौरान ग्राम लक्ष्मणगढ़, ब्लॉक उदयपुर, जिला सरगुजा निवासी आदिवासी युवक कमलेश सिरदार सहित तीन मजदूरों की मौत के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के संसाधनों को मोदी के मित्र अडानी पर लुटाने के लिए आदिवासी हितों के खिलाफ षड़यंत्र रच रही है। अडानी के मुनाफे के लिए हसदेव अरण्य जंगल में अवैध कटाई खुद भाजपा की सरकार करवा रही है और विरोध करने वाले आदिवासियों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं।

केंद्र की मोदी सरकार वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन के अधिकार से वंचित कर रही है। अपने कॉर्पोरेट मित्रों के मुनाफे के लिए कमर्शियल माइनिंग शुरू किये, कोल बेयरिंग एक्ट में संशोधन किया, अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जिसमें छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और तमोर पिंगला का क्षेत्र भी शामिल था वहां पर नो गो एरिया को संकुचित करके अपने पूंजीपति मित्र को कमर्शियल मीनिंग की अनुमति दी और उसे लागू करने संगीनों के साए में यह सरकार अवैध कटाई करवा रही है।

तीन-तीन मजदूरों की मौत पर सरकार की खामोशी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि यह सरकार कितनी मजबूर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई है। पहले ग्राम सभा की फर्जी एनओसी लगाकर, भारी जनविरोध के बाबजूद नंदराज पर्वत अडानी को दिए, पूर्ववती कांग्रेस की सरकार ने लीज निरस्त करने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके मोदी सरकार को भेजा लेकिन अब तक निरस्त नहीं किया गया है.

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से 'गुड गवर्नेंस' विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन

देश भर के 150 प्रतिनिधि होंगे शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 और 22 नवम्बर को ''गुड गवर्नेंस'' विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण,

शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह इस क्षेत्रीय सम्मेलन के 22 नवम्बर को आयोजित समापन सत्र को सम्बोधित करेंगे। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और छत्तीसगढ़ के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से 150 प्रतिनिधियों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल होंगे। क्षेत्रीय सम्मेलन में नवाचार-राज्य, जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व, जिलों का समग्र विकास, ''छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोत्तम प्रथाएं'', ''जिलों के समग्र विकास में संतृप्ति दृष्टिकोण'' आदि विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रथम दिन 21 नवम्बर को सवेरे 10 बजे ''नवाचार-राज्य'' विषय पर प्रथम सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र की अध्यक्षता भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एस.एन. त्रिपाठी करेंगे। पूर्वान्ह 11 बजे उद्घाटन सत्र आयोजित होगा। इस सत्र को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन सम्बोधित करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे ''जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व'' विषय पर द्वितीय सत्र आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता छत्तीसगढ़ सरकार के वन और खाद्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा करेंगी।

राजधानी में ईडी का छापा, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है मामला

पूरा मामला बिटकाइन से जुड़ा हुआ है

रायपुर। राजधानी में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी ने गौरव मेहता के ठिकानों पर दबिश देते हुए छापामार कार्रवाई की है। पूरा मामला बिटकाइन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में गौरव

का नाम सामने आने के बाद ईडी एक्शन मोड पर है।

गौरव मेहता एक कंसल्टेंसी के लिए काम करता है। यह कंसल्टेंसी महाराष्ट्र की पुणे पुलिस को अमित भारद्वाज के 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले की चल रही जांच में मदद कर रही थी। मंगलवार को पूर्व आईएएस रविंद्रनाथ पाटिल ने दावा किया था कि गौरव मेहता से सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने संपर्क किया था। महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव में उपयोग के लिए बिटकाइन नकद की मांग की थी।

ईडी ने राजधानी रायपुर स्थित मेहता के ठिकानों पर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत छापामार कार्रवाई की है। जो अब भी जारी है। इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गरमाई हुई है। राजधानी से लेकर समूचे छत्तीसगढ़ में भी ईडी की इस कार्रवाई की चर्चा छिड़ी हुई है।

भाजपा ने लगाया था आरोप

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने एनसीपी शरद पवार की नेता एवं बारामती लोकसभा सीट से सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर विधानसभा चुनाव में अवैध रूप से बिटकाइन के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। भाजपा के नेताओं ने आरोपों की पुष्टि के लिए आडियो रिकार्डिंग जारी किया था जिसमें सुप्रिया सुलेकी आवाज होने का आरोप लगाया है।

अम्बेडकर अस्पताल में 1 दिसंबर से खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र

रायपुर। रायपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने पं. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के स्वशासी समिति की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक ली। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए है। अम्बेडकर अस्पताल में 1 दिसंबर से नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा। इसका संचालन चिकित्सालय के मनोरोग विभाग द्वारा किया जाएगा।

इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वशासी बजट के अंतर्गत अभी तक हुए आय-व्यय की समीक्षा की गई। बैठक में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अम्बेडकर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने जानकारी दी कि चिकित्सालय के किराया कक्षों (पेइंग वार्डों) के नवीनीकरण हेतु 26 एसी, केजुअल्टी विभाग हेतु 09 एसी और सीटीवीएस विभाग हेतु 05 एसी के क्रय की प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। डॉ. सोनकर ने बताया कि चिकित्सालय में साइनेज बोर्ड लगाये जाने एवं अन्य नवीनीकरण कार्य करवाये जाने से संबंधित प्रस्ताव कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित किया जा चुका है।

चिकित्सालय के रेडियोडायग्नोसिस

विभाग के लिए एक प्रेशर इंजेक्टर मशीन के क्रय की कार्यवाही सीजीएमएससी द्वारा की जा रही है। यह मशीन सीटी स्कैन, एमआरआई और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के लिए बेहद उपयोगी है। चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चैधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत बैठक में फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के अंतर्गत होने वाले पोस्टमार्टम कार्य हेतु एक नग नवीन वर्चुअल पोस्टमार्टम मशीन के क्रय किये जाने की अनुशंसा की गई थी जिसके अंतर्गत वर्तमान में मशीन का स्पेसिफिकेशन तैयार किया जा रहा है।

वर्चुअल पोस्टमार्टम मशीन के लिए संबंधित फर्म को बुलाकर पहले उसका डेमोंस्ट्रेशन लिया जाएगा। उसके बाद क्रय हेतु सीजीएमएससी को मांगपत्र भेजेंगे। डॉ. चौधरी द्वारा जानकारी दी गई कि नवीन स्वशासी नियमावली में अन्य आकस्मिक व्यय हेतु अधिष्ठाता एवं अधीक्षक को 5 लाख रुपये तक स्वीकृति एवं भुगतान की वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है। इसके साथ ही प्रबंधकारिणी समिति को प्रतिकार्य 2 करोड़ रुपये तथा वित्त समिति को प्रतिकार्य 10 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। चिकित्सालय के उपयोग हेतु 02 नग ए. एल. एस. एम्बुलेंस शीघ्र क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया। चिकित्सालय के मनोरोग विभाग में आगामी 01 दिसंबर से नशा मुक्ति केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.